सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivehanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 01, नई दिल्ली | शुक्रवार, 17 मार्च 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

हर दिन अच्छा हो ये जरुरी नही होता. पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरुर होता है.

इनसाइड

दिल्ली के बाद इस शहर में बंद हो सकती है बाइक टैक्सी...

नई दिल्ली। दिल्ली के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य शहर नोएडा में बाइक टैक्सी को बंद किया जा सकता है. इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. परिवहन विभाग शहर और उसके बाहरी इलाकों में रजिस्टर्ड बाइक टैक्सियों की जांच के लिए एक अभियान चलाने की योजना बना रहा है. परिवहन विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि जिले में 2,446 रजिस्टर्ड बाइक टैक्सी हैं. निजी नंबर वाली बाइक्स को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जाने के आरोपों के बाद अभियान चलाने का कदम उठाया गया है. नियमों के मुताबिक, बाइक टैक्सी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उस पर पीले रंग की नंबर प्लेट होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सियाराम वर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग को कई शिकायतें मिली थीं कि निजी बाइकों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "परिवहन विभाग एक अभियान चलाएगा और कमर्शियल एक्टिविटी में शामिल ऐसे वाहनों को जब्त करेगा.इससे पहले 21 फरवरी को दिल्ली सरकार ने इसी तरह के मुद्दों पर राष्ट्रीय राजधानी में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया. दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-परिवहन (प्राइवेट) रजिस्टर्ड नंबर वाले टू-व्हीलर वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता. पिछले महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ एक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर को राहत देने से इनकार कर दिया था.

वाहनों को कबाड़ में बदलने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं: राजमार्ग मंत्रालय

कृषि ट्रैक्टर, एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरुआत में 15 वर्षों के लिए पंजीकृत है

संजय बाटला

वाहन कबाड़ नीति के तहत गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को हटाने की खबर को झूठा और आधारहीन बताया.

नयी दिल्ली। वाहन कबाड़ नीति के तहत गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को हटाने की खबर को झूठा और आधारहीन बताया.

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि ट्रैक्टर, एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरुआत में 15 वर्षों के लिए पंजीकृत है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 15 साल की शुरुआती पंजीकरण अवधि पूरी होने के बाद इसके पंजीकरण को एक बार में पांच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है.

Child Adoption in India: बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया हुई सरल, अब एडॉप्शन में आई तेजी

मंत्रालय ने कहा, "10 साल बाद ट्रैक्टरों को अनिवार्य रूप से कबाड़ में बदलने के संबंध में ट्विटर और व्हाट्सऐप सहित मीडिया के एक वर्ग में चल रही खबरें पूरी तरह से झूठी, निराधार और बिना किसी सचाई के हैं."

बयान में चेतावनी दी गई कि दहशत पैदा करने के लिए झूठी सूचना फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इनमें आगे कहा गया कि भारत सरकार ने कुछ सरकारी वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन के लिए आयु निर्धारित नहीं की है. मंत्रालय ने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को स्वैच्छिक रूप कबाड़ में बदलने के लिए वाहन कबाड़ नीति तैयार की है.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर बरातियों से भरी बस पलटी, 12 से अधिक घायल

गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर देर रात भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव भटजन पलीता के समीप दिल्ली की तरफ जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए।

रात बिजनौर के नजीबाबाद से कुछ लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए बस से दिल्ली जा रहे थे। बस जैसे ही दिल्ली-मेरठ मार्ग पर गांव भटजन पलीता के समीप पहुंची तभी उसका एक्सेल टूट गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके में अनबन, सौतन, पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों और एक्सप्रेसवे की टीम ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद मौके पर यातायात बाधित हो गया। क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की सहायता से हटाकर यातायात सामान्य कराया गया।

दिल्ली मेट्रो में इंस्टा रील्स, डांस वीडियो बनाने पर रोक...

नई दिल्ली। हाल के समय में दिल्ली मेट्रो के कोच के अंदर इंस्टाग्राम रील और वीडियो बनाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। इसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कोच में वीडियो और रील बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। DMRC की तरफ से वीडियो और रील न बनाने की अपील की गई है। बता दें कि मेट्रो कोच के अंदर रील, वीडियो बनाना किसी एक के लिए लाइक और व्यूज के लिहाज से सही हो सकता है। हालांकि, अन्य यात्रियों को इसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने मेट्रो के अंदर रील, वीडियो बनाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। पहले से भी दिल्ली मेट्रो की ओर से चेतावनी जारी की जाती रही है कि मेट्रो कोच के अंदर वीडियो न बनाएं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अक्सर मेट्रो कोच के अंदर रील बनाने के वीडियो सामने आते रहे हैं। सोमवार को दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को यात्रा के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगाते हुए यही संदेश दोहराया।

देश के विकास की नींव होती हैं सड़कें, जानें कितनी तरह की है रोड, किस पर चलते हैं आप

देश के विकास की नींव होती हैं सड़कें, जानें कितनी तरह की है रोड, किस पर चलते हैं आप किसी भी देश की सड़क उस देश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाती है. भारत भी उन्हीं देशों में से एक है जिसका रोड नेटवर्क पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है. सड़क ही भारत में परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है. तो क्या आप जानते हैं हमारे देश में कितनी तरह की सड़कें होती हैं.

पी.वी. न्यूज

1. एक्सप्रेस-वे (Expressways) : एक्सप्रेस-वे ऐसी सड़कें हैं जिनमें लेन की संख्या अधिक होती है. शानदार सड़कें और जबरदस्त सुरक्षा के साथ इन पर गाड़ियां दोगुनी स्पीड से फर्राटा भर सकती है. इनका निर्माण और रखरखाव कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) द्वारा संचालित किया जाता है.

2. राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) : राष्ट्रीय राजमार्ग वे सड़कें होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से राजमार्ग का दर्जा

मिला होता है. ये मुख्य सड़कें भारत के विभिन्न राज्यों और मुख्य शहरों को जोड़ती हैं. एक नेशनल हाईवे की चौड़ाई आमतौर पर 7 मीटर से 15 मीटर तक होती है.

3. राज्य राजमार्ग (State Highway) : राज्य राजमार्ग मुख्य रूप से किसी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, जिला स्थानों और प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं. इसके अलावा ये आसपास के राज्यों को भी जोड़ती हैं.

4. जिला सड़कें (District Roads) : जिला सड़कें मुख्यतः किसी राज्य के जिला परिषदों, जिला मुख्यालयों, छोटे-बड़े शहरों को जोड़ती हैं, साथ ही राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ती हैं.

5. पंचायत या ग्रामीण सड़कें (Rural Roads) : वे सड़कें जो किसी भी गांव को जिले की सड़कों से जोड़ती हैं, पंचायत या ग्रामीण सड़कें कहलाती हैं. इन सड़कों पर केवल हल्का यातायात करती हैं. ग्रामीण क्षेत्र के विकास में ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी से 330.91 एकड़ जमीन वापस लेगा प्राधिकरण, निर्देश जारी

नोएडा। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट डीएनडी फ्लाई-वे निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को सौंपी गई जमीन में से 330.91 एकड़ अवशेष जमीन वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है। अवस्थापना विभाग ने पत्र जारी कर वर्क सर्किल एक को निर्देशित किया है कि जमीन वापस लेने के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। हालांकि इस प्रकरण की संबंधित फाइल ही नोएडा प्राधिकरण कार्यालय से गायब हो गई है, जिससे वर्क सर्किल एक अधिकारी को इसका जवाब देने और आगे की कार्रवाई को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। वर्क सर्किल एक के वरिष्ठ प्रबंधक डोरी लाल वर्मा का कहना है कि फाइल की तलाश जारी है, फाइल कहां पर है, यह पता करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में जानकारी सर्किल में तैनात किसी कर्मचारी के पास नहीं है। कंपनी को डीएनडी फ्लाई-वे निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से जमीन उपलब्ध कराई गई थी। निर्माण के बाद अवशेष जमीन को वापस लेने के लिए प्राधिकरण की ओर से हवाई सर्वे कराया गया। अवशेष भूमि चिह्नित कर प्राधिकरण को वापस करना सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन हुआ। तत्कालीन मुख्य अभियंता (सिविल) नोएडा की ओर से 5 अगस्त 2016 और 16 अगस्त 2016 को सर्वे रिपोर्ट तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। सर्वे रिपोर्ट में गठित टीम के सदस्य अधिशासी अभियंता, हेड वर्क्स खंड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली द्वारा नामित अधिकारी के अलावा नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लैंड एंड बिल्डिंग विभाग, दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि, मुख्य वास्तुविद नियोजक, नोएडा के हस्ताक्षर नहीं थे।

दिल्ली का बजट 21 मार्च को, 5 से 10 % की वृद्धि

एसठी सेठी

नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व दो मंत्रियों के जेल में बंद होने के बावजूद राजधानी दिल्ली का वित्तीय बजट वर्ष 2023-24 का जेल में बंद मनीष सिसौदिया की जगह नए वित्त मंत्री कैलाश गहलौत 21 मार्च को विधान सभा में पेश करेंगें। हालांकि विधान सभा बजट सत्र 17 मार्च से शुरू होने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो यह बजट पिछले साल की तुलना में 5 से 10 फीसदी तक का इजाफे की खबर है।

बता दें कि बीते साल 75 हजार 800 करोड रूपये का प्रस्तावित बजट पेश किया था। इस बार उम्मीद की जा रही है कि बजट राशि 80 हजार करोड रूपये के आस-पास पहुंच सकती है। माना जा रहा है कि

केजरीवाल पेश बजट में दिल्ली को संवारने की घोषणाएं होने के साथ पुरानी योजनाओ को जारी रखने की घोषणाएं शामिल रह सकते है। दरअसल केजरीवाल सरकार इस फैसले से यह दिखाना चाहती है कि तमाम मुश्किलों और दो वरिष्ठ मंत्रियों के जेल जाने के बाद भी सरकार की योजनाएं नहीं थमेगी। केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2015 में पहली बार बजट पेश किया था। तब महज 30000 हजार करोड रूपये का.था। अब 75 से 80 हजार करोड का हो गया है।

राघवेन्द्र कुमार उर्फ 'हेलमेट मैन' खुद अपनी कार चलाते वक्त भी हेलमेट पहनते हैं....

नौकरी छोडकर फ्री में हेल्मेट बांटना ,सडक सुरक्षा में लगे है 'हेल्मेट मैन' राघवेंद्र कुमार : एक शख्सियत

एसठी सेठी

नई दिल्ली। दोस्त की सडक हादसे में हुई मौत से विचलित एक शख्स ने बिना हेलमेट पहने सडकों पर उतरने वाले बाइकर्स, स्कूटी और स्कूटर सवारों को फ्री में हेलमेट बांटने का जीवन भर का बीडा उठा लिया है। ऐसे कर्मयोगी राघवेन्द्र कुमार की जगह ₹हेलमेट मैन₹ के नाम से तमगा मिल गया है। साल 2014 में दोस्त कृष्णा की मौत एक सडक दुर्घटना में हो गई थी। वह बिना हेलमेट के बाईक चला रहा था।उसकी मौत के सदमें को झेलते हुए ही नौकरी छोड़कर दी और सडक हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दो पहिया चालकों को फ्री में हेलमेट बांटना शुरू किया। तब से अब तक करीब 56000 हेलमेट वह फ्री में बांट चुके हैं। ये तमाम हेलमेट वह सडक पर ही अपनी कार ड्राइव करते समय मिले बिना हेलमेट धारी को हेलमेट पहनाकर सडक सुरक्षा का पैगाम दे रहे हैं।

> राघवेन्द्र ने बाकायदा अपनी कार के पीछे लिखवा रखा है यमराज ने भेजा है, हेलमेट मैन को आपकी सुरक्षा की खातिर ,फ्री में हेलमेट बांटने और ' लोगों की जान बचाने के लिए। सडक सुरक्षा जीवन की रक्षा। राघवेन्द्र उर्फ हेलमेट मैन को इसके लिए 'एशिया एक्सीलेंसी अवार्ड' से भी नवाजा जा चुका है।

बता दें कि राघवेन्द्र कुमार उर्फ 'हेलमेट मैन' खुद अपनी कार चलाते वक्त भी हेलमेट पहनते हैं। आंकडे के मुताबिक भारत में बिना हेलमेट के मौत का आंकडा 50 प्रतिशत तक है। बताते हैं कि विश्वयुद्ध मे जान गंवाने वालों से ज्यादा जानें हर साल भारत की सडक दुर्घटनाओ में जाती हैं। अब तक सडक सुरक्षा का पैगाम वह जन-जन तक पहुंचा चुके है। राघवेन्द्र ने बाकायदा अपनी कार के पीछे लिखवा रखा है यमराज ने भेजा है, हेलमेट मैन को आपकी सुरक्षा की खातिर ,फ्री में हेलमेट बांटने और ' लोगों की जान बचाने के लिए। सडक सुरक्षा जीवन की रक्षा। राघवेन्द्र उर्फ हेलमेट मैन को इसके लिए 'एशिया एक्सीलेंसी अवार्ड ₹से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा एक नई मुहीम के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को राघवेन्द्र पुरानी किताबों को मुहैया करवाते हैं। इसके लिए उन्होने बाकायदा ओल्ड बुक बैंक खोल रखा है। इसी बुक बैंक में जमा हुई किताबों को वह गरीब पढने वाले बच्चौं की सहायता करने का भी बीडा उठा लिया है। हेलमेट समेत फ्री बुक बांटने के लिए उन्होंने अपना नोएडा का मकान तक .बेच दिया है। बता दें कि राघवेन्द्र उर्फ हेलमेट मैन बिहार के एक छोटे से कैमूर गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल वह नोएडा में रह रहे हैं।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

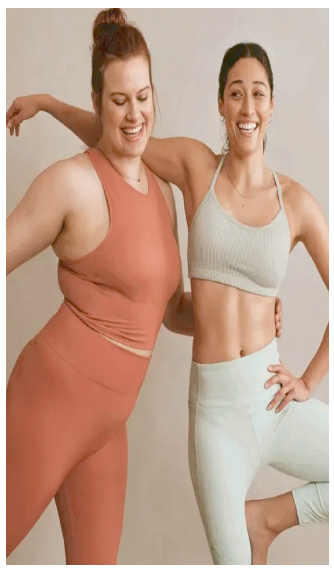

अपनाएं ये बॉडी पॉजिटिविटी टिप्स, खुद से हो जाएगा प्यार

18-30 की उम्र के बीच की 70% महिलाएं अपने शरीर को नापसंद करती हैं और 45% पुरुष भी अपने शरीर से असंतुष्ट हैं. ऐसे में बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है.

शारीरिक बनावट के अलावा अन्य चीजों के बारे में सोचने में अधिक समय बिताएं.

क्या आपने हाल ही में रिलीज़ हुआ 'डबल एक्सेल' का ट्रेलर देखा है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड मूवी डबल XL का ट्रेलर रिलीज हुआ है. इसमें सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी बॉडी शेमिंग करने वालों को करारा जवाब देती नजर आ रही हैं. इसके ट्रेलर में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी दिखाई दे रहे हैं. फिल्म में एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया है जिससे कई लोग वाबस्ता हैं. हालांकि, आज के दौर में बहुत लोगों ने बॉडी पॉजिटिविटी की ओर कदम बढ़ाया है लेकिन आज भी कई लोग, खासकर महिलाएं अपनी बनावट और बॉडी के कारण परेशान रहती हैं. किसी को दुबला तो किसी को मोटा कह कर चिढ़ाया जाता है, जो कि गलत है. जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए हेल्दी बॉडी होने का मतलब भी एक जैसा हो.

रोग मुक्त होने के लिए एक ही तरह की बॉडी आइडियल नहीं होती. हो सकता है एक इंसान की नजर में जो शख्स अस्वस्थ हो, वो असल में हेल्दी ही हो. सबका आकार अलग है और इसमें कुछ गलत नहीं है. आपको बता दें कि वेलबींगट्रस्ट डॉट ओआरजी के अनुसार 18-30 की उम्र के बीच की 70% महिलाएं अपने शरीर को नापसंद करती हैं और 45% पुरुष भी अपने शरीर से असंतुष्ट हैं. अगर आप भी अपने शरीर को लेकर सहज महसूस नहीं करती हैं तो आज हम आपको कुछ बॉडी पॉजिटिविटी टिप्स बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने शरीर को आपका हर रोज साथ देने के लिए धन्यवाद कहने लगेंगी, जो कि जरूरी भी है.

अपनाएं ये बॉडी पॉजिटिविटी टिप्स

पॉजिटिव अफर्मेशन्स बोलें

बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है. इसका अभ्यास करने के सबसे बुनियादी और प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन्स को ज़ोर से बोलें, खासकर जब हम अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस न कर पा रही हों. खुद से कहें- 'मैं काफी हूं', 'मैं सुंदर हूं', 'मैं किसी से कम नहीं हूं', 'मैं हर हाल में और हर तरह से खूबसूरत हूं'.

उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको अपने बारे में हैं पसंद

हर बार जब आपके दिमाग में आपके शरीर के बारे में कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसका मुकाबला कुछ सकारात्मक सोचकर करें. उन चीजों की लिस्ट बनाने की कोशिश करें जो आपको अपने शरीर के बारे में पसंद हैं.

दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें

लोगों की शेप अलग-अलग होती है. एक इंसान एक तरह से खूबसूरत होता है तो दूसरा इंसान किसी और तरह से अच्छा लग सकता है. दूसरों से अपनी तुलना करने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप वैसे नहीं दिखते जैसे आपको दिखना चाहिए लेकिन आपको किसी और की तरह नहीं दिखना है क्योंकि सब एक जैसे दिखाई देंगे तो यह बहुत बोरिंग लग सकता है.

नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें

अपने शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी मित्र के साथ करते हैं. अगर आप अपने शरीर के बारे में जो कुछ भी कहते हैं वैसा कुछ आप अपने किसी दोस्त के बारे में या उसके शरीर के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत होगा तो ऐसा अपने साथ भी मत कीजिए. नेगेटिव सेल्फ टॉक ही हमें शरीर के लिए नकारात्मक सोचने पर मजबूर करती है.

प्रेग्नेंसी में मॉर्निंग सिकनेस से हैं परेशान? काम के हैं ये 5 नेचुरल तरीके

प्रेग नेंसी के दौरान महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या मॉर्निंग सिकनेस और बार-बार होने वाली उल्टियां होती हैं. हालांकि, शोधों में ये पाया गया है कि प्रेग नेंसी में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हेल्दी प्रेग नेंसी की निशानी है.

प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीनों में मॉर्निंग सिकनेस, मिचली और उल्टी आना काफी आम लक्षण हैं. इसकी वजह महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने और ब्लड शुगर का लो होना कहा जा सकता है. ऐसे में कई महिलाएं किसी खास तरह के गंध को लेकर संवेदनशील हो जाती हैं और बार-बार उल्टी आने की समस्या उन्हें परेशान करने लगती है. हालांकि, यह भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंसी में उल्टियां होना खतरनाक नहीं होता, बल्कि इसे हेल्दी प्रेग्नेंसी का लक्षण कहा जा सकता है. अगर अधिक मात्रा में उल्टी होने लगे तो शरीर में पानी और न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है. हम आपको बताते हैं कि आप बिना दवाओं के प्रेग्नेंसी के दौरान उल्टियों को किस तरह रोक सकती हैं.

कम मात्रा में पानी पिएं- मेडिकल न्यूज टुडेके मुताबिक, प्रग्नेंसी के दौरान पानी का पर्याप्त सेवन काफी जरूरी होता है. अगर आप थोड़ा-थोड़ा पानी नियमित रूप से पिएं तो इससे शरीर में हाइड्रेशन की कमी नहीं होती और उल्टी नहीं आती.

कम मात्रा में खाएं- अगर आप एक बार में भर पेट खाना खाती हैं तो ये प्रेग्नेंसी में बार-बार उल्टी की वजह बन सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप कम मात्रा में, लेकिन कुछ-कुछ देर में खाती रहें. यही नहीं, स्पाइसी खानों से भी अभी दूरी बनाकर रखें. अगर आप सुबह उठकर एक सेव या केला खा लें तो सुबह उल्टी जैसा अनुभव नहीं होगा. कुछ कुछ घंटे पर हेल्दी स्नैक्स लें.

ट्रिगर को पहचानें- अगर आप यह पहचान लें कि किसकी खुशबू या क्या खाने से आपको उल्टी आती है तो आप अपनी समस्या को दूर कर सकती हैं. मसलन, बाथरूम में रखा रूम स्प्रे, किसी खास तरह का साबुन, किचन में खाने की कोई खास चीज आदि.

पिएं अदरक की चाय- प्रेग्नेंसी में अदरक की चाय आपके पेट की समस्याओं और जी मिचलाने जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. ऐसे में आप प्रेग्नेंसी के दौरान मतली या उल्टी से बचने के लिए दिनभर में एक या दो बार जरूर अदरक की चाय पी सकती हैं. आप अदरक कैंडी या अदरक का एक टुकड़ा भी चबाकर आराम पा सकती हैं.

सौंफ का करें सेवन- प्रेग्नेंसी में आप सौंफ या सौंफ की चाय या काढ़ा पी सकती हैं. ये पेट में बनने वाले गैस को दूर करता है और आप बेहतर महसूस करती हैं. आप इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में भी खाने के बाद इस्तेमाल कर सकती हैं.

कम उम्र में महिलाएं हो रही हैं हार्ट अटैक का शिकार

आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं ज्यादातर सामने आ रही हैं जिनमें खराब लाइफस्टाइल की आदतें और बढ़ता मोटापा या अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कारण शामिल हैं.

आजकल की भागदौड़ भरी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना एक आम समस्या बन गई है. यह एक ऐसी गंभीर स्थिति है जो अक्सर लोगों की जान ले सकती है. हार्ट अटैक के सबसे सामान्य लक्षण सीने में दर्द या दबाव महसूस होना होते हैं. यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है. एक्सपर्ट्स की माने तो यह समस्या कम उम्र के लोगों और खासकर महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिल रही है. यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि वृद्धो में दिल के दौरे के दर में कमी आयी है और यही संख्या युवाओ में बढ़ी है. इसमें भी खासकर महिलाओं को हार्ट अटैक ज्यादा प्रभावित कर रहा है.

महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या होने के कारणों में हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज और मोटापा आदि हो सकते है. आइए जानते हैं

महिलाओं में हार्टअटैक की समस्या होने के कारण

हाई ब्लड प्रेशर

हॉपकिंस मेडिसिन डॉट ओआरजी के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के कारण महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल सकती है. हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं. लाइफस्टाइल की कुछ गलत आदतों के कारण या महिलाओं में गर्भावस्था और बर्थ कंट्रोल पिल्स हाई ब्लड प्रेशर होने के रिस्क को बढ़ा देती है अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के साथ-साथ स्मोक भी करती हैं तो इससे ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना अधिक हो जाती है.

हाई कोलेस्ट्रॉल

एस्ट्रोजन महिलाओं को एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाने का काम करता है लेकिन मेनोपॉज़ जैसी स्थिति के बाद एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है और हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना अधिक हो जाती है. हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण महिलाओं में हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है.

स्मोकिंग

स्मोकिंग करने से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है. ऐसे में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में स्मोकिंग करने वाले पुरुषों की तुलना में हार्ट डिजीज विकसित होने का खतरा और ज्यादा अधिक होता है.

निकोटीन आपकी बॉडी के सभी भागों जैसे हार्ट और ब्लड वेसल्स से लेकर आपके हार्मोंस, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन तक, को प्रभावित कर सकता है.

महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या होने के अन्य कारणों में डायबिटीज, मोटापा, जेनेटिक्स हार्ट समस्याएं, उम्र, अत्यधिक शराब का सेवन और खराब लाइफस्टाइल शामिल हो सकते हैं.

महिलाओं के लिए नौकरी की तुलना में सेल्फ एम्प्लॉई होना ज्यादा फायदेमंद! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

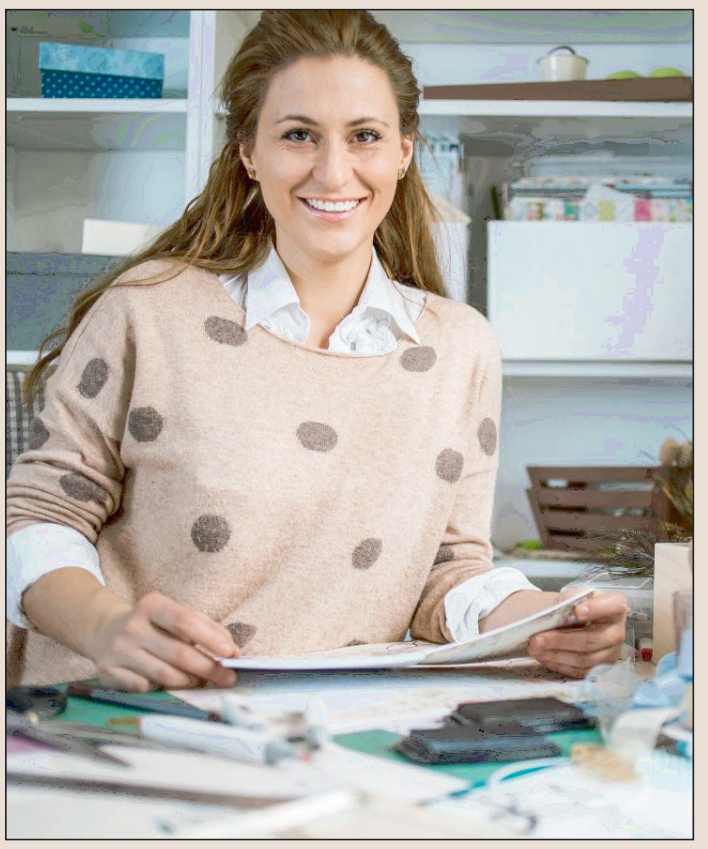

शोधों में पाया गया कि जो महिलाएं सैलरी लेती हैं या किसी और के लिए काम करती हैं, उनमें हृदय रोग, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलीं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉई महिलाएं अधिक फिट और हेल्दी पाई गईं.

आमतौर पर यह माना जाता है कि नौकरी करना बिजनेस करने की तुलना में कम स्ट्रेसफुल होता है. यही वजह है कि महिलाएं नौकरी करना अधिक सेफ समझती हैं, लेकिन नए शोध में यह पता चला है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो यह आपकी सेहत के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है. नए शोध के मुतबिक, खासतौर पर अगर महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉई यानी स्व-नियोजित हैं तो उनमें हार्ट से जुड़ी बीमारियां, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा होने की संभावना कम पाया गया है.

यही नहीं, जो महिलाएं मजदूरी कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं, उनकी तुलना में सेल्फ एम्प्लॉई महिलाओं का शारीरिक गतिविधि अधिक रहता है, जिस वजह से उनकी सेहत भी बेहतर रहती है. हेल्थ हार्वर्ड में छपे आलेख के मुतबिक, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एमिली लाउ का इस विषय पर कहना है कि अध्ययन से पता चलता है कि दरअसल, महिलाओं को अपने रोजगार का प्रभार लेने और उनके काम करने के तरीके, उनकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

क्या कहना है शोध का

2016 और 2018 के बीच किए गए इस शोध में करीब 4,624 महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया और इनके आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया जिसमें वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-नियोजित या मजदूरी के लिए काम करने वाली थीं. ये सभी 50 वर्ष से अधिक आयु की थीं और लगभग 16% प्रतिभागी सेल्फ इम्प्लॉई थीं जबकि बाकी सैलरी पानी वाली थीं. इनमें पाया गया कि जो महिलाएं सैलरी लेती हैं या किसी और के लिए काम करती हैं, उनमें हृदय रोग, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिली.

क्या पाया गया शोध में

अध्ययन में पाया गया कि स्वरोजगार करने वाली महिलाओं में मोटापे की संभावना 34% कम पाई गई, उच्च रक्तचाप की संभावना 43% कम थी और वेतन या मजदूरी के लिए काम करने वालों की तुलना में मधुमेह की संभावना 30% कम दिखी. इस बीच, स्व-नियोजित महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) कम था और वे अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय थीं. जबकि 80% महिलाओं ने कहा कि वे अन्य प्रतिभागियों के 72% की तुलना में सप्ताह में कम से कम दो बार व्यायाम करती हैं. ये सारी चीजें हार्ट के हेल्थ को काफी हद तक प्रभावित करते हैं.

घरेलू कामकाज के बोझ से दबी भारत की शहरी महिलाएं, 53 फीसदी दिन भर में एक बार भी घर से नहीं निकलतीं बाहर : स्टडी

अक्सर महिलाएं अपने घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि उनके पास खुद पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं रहता है. ना तो वो ठीक से अपनी सेहत का ध्यान रख पाती हैं, ना खुद को समय दे पाती हैं और ना ही घर से बाहर निकल कर अपनी मर्जी से घूम-फिर पाती हैं. आज भी घर से बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं की संख्या हाउस वाइफ की संख्या से काफी कम है. इससे भारत कई जेंडर गैप सूचकांकों में सबसे नीचे है. महिलाओं की संख्या आज भी मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में बेहद कम है. ये जॉब हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. इसका मतलब है कि आज भी अधिकतर महिलाएं काम पर नहीं, बल्कि घर पर मौजूद हैं. ऐसा हम नहीं, बल्कि हाल ही में हुए एक अध्ययन में कहा गया है.

दप्रिंट डॉट इन में छपी एक खबर के अनुसार, साइंस डायरेक्ट की पत्रिका ट्रैवल बिहेवियर एंड सोसाइटी में इस अध्ययन को 'जेंडर गैप इन मोबिलिटी आउटसाइड होम इन अर्बन इंडिया' शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया. अध्यययन में ये बात सामने आई है कि शहर में रहने वाली (Urban India) लगभग आधी महिलाओं ने कहा कि वे दिन में एक बार भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलती हैं. आईआईटी दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर के राहुल गोयल द्वारा लिखित अध्ययन में ये कहा गया है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच मोबिलिटी की तुलना की जाए तो इसमें व्यापक अंतराल है, जो अपने आप में दुनिया भर में बेहद 'दुर्लभ' बात है.

अध्ययन का रिजल्ट चौंकाने वाला

राहुल गोयल द्वारा किया गया अध्ययन शहरी भारत पर केंद्रित है, जिसमें लगभग 84,207 महिलाएं और 88,914 पुरुषों को शामिल किया गया. अध्ययन के अनुसार, सामान्य दिन में सिर्फ 47 प्रतिशत महिलाओं ने दिन में कम से कम एक बार अपने घरों से बाहर निकलने की जानकारी दी. इसका मतलब है कि करीब 53 फीसदी महिलाएं सामान्य दिन में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं. दिन में कम से कम एक बार बाहर निकलने की सूचना देने वाले पुरुषों का अनुपात लगभग 87 प्रतिशत था. इसका मतलब ये है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष घर पर बहुत कम रहते हैं.

फैक्टर्स जिनके कारण महिलाएं निकलती हैं कम

अध्ययन में महिलाओं से चर्चा करने के बाद कई कारकों का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से महिलाएं घर से कम निकलती हैं. इसमें एक बात सामने आई है कि महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए ठोस कारणों की आवश्यकता होती है, जो पुरुषों के लिए जरूरी नहीं है. पढ़ाई-लिखाई करने वाली 81 प्रतिशत महिलाओं ने दिन भर में घर से एक बार बाहर जाने की जानकारी दी. पुरुषों के साथ ऐसा नहीं पाया गया. वहीं, लगभग 81 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं ने दिन में एक बार घर से बाहर जाने की जानकारी दी.

ऐसी महिलाएं जो न तो नौकरी करती हैं और ना ही पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं, उनमें 30 प्रतिशत ने ही दिन में घर से बाहर निकलने की बात कही. इसका मतलब साफ है कि करीब 70 फीसदी महिलाएं दिन में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकलती हैं. दूसरी ओर, सिर्फ 35 प्रतिशत काम नहीं करने वाले पुरुष ही घरों में रहते हैं.

महिलाएं घर के कामों में रहती हैं उलझी

आंकड़ों से पता चला कि 52 प्रतिशत से अधिक महिलाएं घरेलू कामकाज में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत करती हैं. इसमें खाना बनाना, साफ-सफाई, घर की साज-सज्जा आदि काम शामिल हैं. बिना किसी सैलरी यानी अवैतनिक श्रम (Unpaid labour) पर इतना समय खर्च करने वाले पुरुषों की संख्या सिर्फ 1.5 प्रतिशत थी. गोयल के अनुसार, चूंकि, महिलाएं घर पर बहुत सारी एक्टिविटीज में व्यस्त रहती हैं, इसलिए उनके लिए घर से बाहर की एक्टिविटीज, काम को कर पाना संभव नहीं हो पाता.

ट्राइसिटी में दौड़ेगी मेट्रो, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की मंजूरी, देखें खर्च और पूरा रूट

चंडीगढ़ के ट्रैफिक के लिए रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा (राइट्स) ने एक कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) बनाया है। इस प्लान में मेट्रो चलाने के अलावा कई जगह फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने समेत कई सुझाव दिए गए हैं। इस प्लान पर एक सहमति बनाने के लिए यूटी प्रशासन ने यह बैठक रखी है।

नईदिल्ली। मोहाली-पंचकूला और चंडीगढ़ में मेट्रो चलाने की चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंजाब की मंत्री अनमोल गगन मान समेत दोनों राज्यों के मुख्य सचिव व अन्य की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें सभी ने ट्राइसिटी में मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी। हालांकि हरियाणा ने मेट्रो स्टेशन को लेकर कई सुझाव दिए हैं जबकि पंजाब ने एक हफ्ते का समय मांगा है।

चंडीगढ़ समेत ट्राइसिटी में बढ़ रहे ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा (राइट्स) ने एक कंप्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) बनाया है। इसमें मेट्रो चलाने, कई जगह फ्लाईओवर-अंडरपास बनाने, कई किमी साइकिल ट्रैक, कई बस स्टैंड, मल्टीलेवल पार्किंग समेत कई सुझाव दिए हैं। गुरुवार को चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा ने इस रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

रिपोर्ट के अनुसार ट्राइसिटी में दो फेज में मेट्रो और तीन फेज में अन्य सभी काम पूरे करने हैं। मेट्रो का कुल खर्च 7680 करोड़ रुपये प्रस्तावित है लेकिन हरियाणा के सुझाव के बाद कई मेट्रो स्टेशन बढ़ जाएंगे। इससे मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाएगी। हालांकि राइट्स के सभी सुझावों को लागू करने में केंद्र सरकार, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के करीब 10,570 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 60 फीसदी पैसा केंद्र और 40 फीसदी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा देंगे।

दो फेज में ऐसे बनेगी मेट्रो (प्रस्तावित)

शहर	फेज-1 (किमी)		फेज-2 (किमी)	कुल (किमी)
चंडीगढ़	14.5	--	14.5	
पंचकूला	3.5	4.5	8.0	
मोहाली	20.0	5.5	25.5	
कुल	38	10	48	

मेट्रो का खर्च (प्रस्तावित)

शहर	फेज-1 (वर्ष 2037 तक)		फेज-2 (वर्ष 2052 तक)	कुल
चंडीगढ़	2320 करोड़	---	2320 करोड़	
पंचकूला	560 करोड़		720 करोड़	1280 करोड़
मोहाली	3200 करोड़	880 करोड़		4080 करोड़

हरियाणा के सीएम ने दिया चंडीगढ़ और जीरकपुर से पिंजौर-कालका से जोड़ने का सुझाव

मेट्रो स्टेशन को लेकर बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कई सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और जीरकपुर से पिंजौर-कालका को जोड़ा जाए और इसे पहले फेज में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही पंजाब-हरियाणा सचिवालय, विधानसभा, हाईकोर्ट, एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पहले फेज में ही मेट्रो से जोड़ा जाए।

बैठक में हाउसिंग बोर्ड चौक से पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई के लिए रूट बनाने का भी सुझाव दिया गया है क्योंकि रोजाना हजारों लोग अपने काम के लिए पीजीआई जाते हैं। इसके अलावा मेट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकूला के इलाकों को भी शामिल करने और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो का वैकल्पिक रूट बनाने का सुझाव दिया गया।

सीएमपी के कामों की निगरानी के लिए बनेगा यूएमटीए

बैठक में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (यूएमटीए) की स्थापना पर भी सहमति बनी है जो सीएमपी के तहत अगले कई वर्षों तक चलने वाले कामों की निगरानी करेगा। यह एक एकीकृत मंच होगा, जिसमें भारत सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हितधारकों को शामिल किया जाएगा। यह अथॉरिटी विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी काम करेंगे।

15 दिन में केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव

राइट्स की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब आगे का काम शुरू किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने जो सुझाव दिए हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। पंजाब की तरफ से भी एक हफ्ते में सुझाव आ जाएंगे। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि 15 दिन में केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव को भेज दिया जाए। - धर्मपाल, सलाहकार, यूटी प्रशासक।

सबसे पहले सेक्टर-26 मंडी से आईएसबीटी पंचकूला तक चलेगी मेट्रो

राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो दो फेज में चलाने की बात कही गई है। फेज-एक में सेक्टर-26 की ग्रेन मार्केट चौक से पंचकूला आईएसबीटी तक करीब 18 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने का प्रस्ताव है। इसके बाद सेक्टर-43 आईएसबीटी से जीरकपुर तक 20 किलोमीटर का ट्रैक होगा। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें आईएसबीटी पंचकूला से पंचकूला एक्सटेंशन तक साढ़े चार किमी तक मेट्रो चलेगी फिर एयरपोर्ट चौक से गांव सनेटा तक मेट्रो जाएगी। इस ट्रैक की लंबाई करीब साढ़े पांच किलोमीटर होगी।

शॉर्ट टर्म प्लान जंक्शन सुधार, नई बस खरीदने और मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात

राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में शॉर्ट, मीडियम और लांग टर्म के लिए कई सुझाव दिए हैं। शॉर्ट टर्म के सुझावों को लागू करने के लिए पांच साल का समय दिया गया है। इसमें वर्तमान इंटरसेक्शन और जंक्शन सुधार, उच्च घनत्व बस कॉरिडोर, नई बस खरीद, बस टर्मिनल सुधार, मल्टी लेवल पार्किंग स्थल का प्रावधान, गैर मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) के लिए योजनाएं, साइकिल ट्रैक का प्रावधान, फुटपाथ का सुधार जैसे कई सुझाव दिए हैं। ये भी बताया है कि इन सुधारों को कहां-कहां जरूरत है।

मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान: मेट्रो और नए लिंक रोड बनाने का सुझाव

राइट्स ने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में चंडीगढ़ समेत मोहाली और पंचकूला में बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का सुझाव दिया है। इसके लिए वर्ष वर्ष 2037 और वर्ष 2052 तक का लक्ष्य रखा गया है।

ब्रीफ न्यूज

जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस इन तारीखों में रहेगी निरस्त, घर से निकलने से पहले दें ध्यान

नई दिल्ली। जयनगर से दिल्ली होते हुए अमृतसर जाने वाली 04651/04652 नंबर की विशेष ट्रेन अगले कुछ दिनों तक निरस्त रहेगी। इससे इस ट्रेन में पहले से सीट आरक्षित कराकर यात्रा की योजना बनाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में ट्रैक दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। इस कारण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रेलवे अधिकारी के अनुसार पहले जयनगर-अमृतसर विशेष ट्रेन के मार्ग में बदलाव करने की घोषणा की गई थी। अब इसे निरस्त करने का फैसला किया गया है।

इन तारीखों में निरस्त रहेगी ट्रैन

जयनगर से चलने वाली यह ट्रेन 17, 19, 21, 24, 26, 28 व 31 मार्च, दो, चार, सात व नौ अप्रैल को निरस्त रहेगी। वापसी दिशा से अमृतसर से इसे 17,19,22,24,26,29 व 31 मार्च, दो, पांच, सात व नौ अप्रैल को नहीं चलेगी।

ट्रेन के निरस्त रहने पर होगी परेशानी

ट्रेन निरस्त किए जाने से यात्रियों को पेरशानी होगी, क्योंकि इन दिनों अधिकांश ट्रेनों में भीड़ है। कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी हो रही है। पूर्व दिशा की ट्रेनों में ज्यादा भीड़ है। कई स्थानों पर चल रहे संरक्षा व निर्माण कार्य से ट्रेनें निरस्त हो रही हैं। कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव कर दिया जा रहा है।

दिल्ली बन रही राममय: कपिल खन्ना

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2080 के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली द्वारा पूरी दिल्ली में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका शुभारंभ नरेला के रामलीला मैदान में भव्य कलश यात्रा और दीदी मां साध्वी रितंभरा जी के श्रीमुख से प्रभु श्री राम जी कथा के रूप में हुआ।

प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने बताया इस सुअवसर पर अपर जनसमूह उपस्थित था जिसमे सभी जाति, बिरादरी और पंथों के लोग शामिल थे। कलश यात्रा में माताओं बहनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रभु श्रीराम की कथा का रसपान करते हुए सभी आनंद से सराबोर हो रहे थे। उन्होंने बताया पूरी दिल्ली में हिंदू नवर्ष और रामनवमी के उपलक्ष्य में इसी प्रकार 1000 से ज्यादा स्थानों पर रामोत्सव के कार्यक्रम रहेंगे जिनमे कही भजन संध्या, कहीं गोष्ठी, कहीं समरसता रैली, कहीं शोभायात्रा, कही सत्संग एवं कीर्तन के कार्यक्रम होंगे जिनमे पूरी दिल्ली का हिंदू समाज भाग लेगा और पूरी दिल्ली राममय बन जायेगी।

दीदी मां साध्वी रितंभरा ने प्रभु श्री राम की कथा का शुभारंभ करते हुए विश्व हिंदू परिषद को इस आयोजन के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने की सभी को बधाई दी और हिंदू समाज से एक ही वाद के नीचे आने को कहा।

उन्होंने जातिवाद, प्रांतवाद और प्रतिवाद आदि से ऊपर उठकर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के नीचे आने आकर समस्त हिंदू समाज को एक होने का आह्वान किया।उन्होंने बताया आज कलश यात्रा में 5000 से ज्यादा बहनों को भागीदारी रही। दुर्गावाहिनी और मातृशक्ति की बहनों द्वारा इस कलश यात्रा की योजना बनी जिसमे पूरे नरेला की बहनों ने भाग लिया।नरेला के रामलीला मैदान में हो रही राम कथा विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के तत्वावधान में नरेला जिला द्वारा आयोजित की जा रही है। यह कथा 21 मार्च तक रहेगी और 22 मार्च को कवि सम्मेलन भी होगा। इस सुअवसर पर प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना, विभाग अध्यक्ष नरसिंह, प्रांत सेवा प्रमुख तोताराम, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गर्ग एवं जिला मंत्री राजेश जैन सहित नरेला जिले के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

ई-फॉरमेसी: अब बंद होगी, दवाई की दुकानें ,सरकार ला रहीं हैं नया कानून

सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ऑनलाईन दवा बिक्री करने वाली कंपनियों के खिलाफ विधेयक कई मंत्रालयों को सौंपा है। ताकि जल्द ही इस पर नया कानून लागू किया जा सके।

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ऑन लाइन दवाएं मंगाने और बेचने वाली तमाम दुकानों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून लाने जा रही है। जिसके बाद देश में ऑनलाइन संचालित सभी दुकानों पर ताला लगाने की पूरी तैयारी है। ऑनलाइन दवा की दुकानों को बंद करने के पीछे सरकार ने मुख्य कारण बताया है कि इससे दवा मंगाने वाले शख्स का डाटा स्टोर किया जा रहा है ।जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने लगभग 20 से ज्यादा ई-फारमेसी कंपनियों को नोटिस भी भेजा है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ऑनलाईन दवा बिक्री करने वाली कंपनियों के खिलाफ विधेयक कई मंत्रालयों को सौंपा है। ताकि जल्द ही इस पर नया कानून लागू किया जा सके। मंत्री समूह का मत है कि ई-फारमेसी से सबसे ज्यादा खतरा निजी जानकारी से है। जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए डिजिटल चलने वाली दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। इसके प्रमुख कारणों में दवा कंपनियों से व्यक्तिगत निजी जानकारी स्टोर की जा रही है ।वहीं कस्टमर्स से अनाब-शनाब पैसा भी वसूला जा रहा है ।यही नहीं बिना चिकित्सक की पर्ची के खरीदी गई दवाएं सेहत के लिए भी हानिकारक साबित हो रही है ।देश में लाखों लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला है। एक सर्वे के मुताबिक अबॉर्शन की ऑनलाईन दवाएं महिलाओ को कम उम्र में ही बांझपन की समस्या से जूझ रही है। इसका कारण आनलाईन दवा मार्केट है। सरकार का मानना है कि आनलाईन दवा बेचने वाली कंपनियां रोगी का डाटा स्टोर करती है। पिछले साल 20 ई-फार्मसी कंपनियों को सरकार ने नोटिस भी भेजे थे ।सरकार द न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज एंड कास्मेटिक बिल 2023 को लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द आधिकारिक सर्कुलर भी जारी कर दिया जाएगा।

सभापुर गांव में प्रॉपर्टी डीलरों ने हाइटेंशन लाइन के नीचे काटी कालोनी, एसडीएम ने रुकवाया काम

नई दिल्ली। सभापुर गांव में प्रापर्टी डिलरों ने हाइटेंशन लाइन के नीचे अवैध रूप से कालोनी काट दी। प्लाटिंग करके लोगों को बेचनी शुरु कर दी। जब इसकी भनक करावल नगर के एसडीएम संजय सोंधी को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और कालोनी का काम बंद करवाया। एसडीएम ने सोनिया विहार थानाध्यक्ष व शाहदरा उत्तरी जोन के निगम उपायुक्त संजय मिश्रा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संजय सोंधी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव में ११० केवी की हाइटेंशन लाइन है। कानून हाइटेंशन तार के नीचे रिहायशी क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता। कानून का उल्लंघन कर अवैध रूप से कालोनी काटी गई है, लोगों को प्लाट बेचे जा रहे हैं। जबकि प्लाट खरीदने वाले लोगों को यह नहीं मालूम की हाइटेंशन लाइन की वजह से बिजली के मीटर का कनेक्शन तक उन्हें नहीं मिल पाएगा। लोगों की भावनाओं से खेलकर प्रापर्टी डिलर रुपया अपनी जेबों में भर रहे हैं। एसडीएम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो कई लोग प्लाट की बाउंडरी करते हुए मिले, उन्होंने अवैध कालोनी में हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया।

सरदार देवेंद्र सिंह को हरियाणा सरकार के द्वारा जिला स्पेशल टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन फरीदाबाद का सदस्य बनाने पर हमारे आदरणीय वाइस चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी स्पेशल टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा सरकार का एवं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री मनोहर लाल खट्टर जी एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं

दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर निर्माण कार्य के चलते लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है

गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर निर्माण कार्य के चलते लोग झेल रहे जाम...

दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर निर्माण कार्य के चलते लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मार्ग पर भयंकर जाम रहा। वहीं रात सात बजे के बाद गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर भीषण जाम लग गया।

नई दिल्ली। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर निर्माण कार्य के चलते लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दिल्ली से गुरुग्राम की ओर जाने वाले मार्ग पर भयंकर जाम रहा। वहीं, रात सात बजे के बाद गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर भीषण जाम लग गया। हालांकि, इसके बीच यातायात की स्थिति सामान्य रही।

वहीं, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नेहरू प्लेस से आइआइटी की ओर जाने वाले कैरिजवे के बंद होने से नेहरू प्लेस लेकर चिराग दिल्ली फ्लाईओवर तक लोगों को जाम से जूझना पड़ा रहा है। खानपुर से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर और मूलचंद फ्लाईओवर से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर की ओर आने वाले मार्ग पर भी जाम का झाम झेलना पड़ रहा है।

विशेषकर ग्रेटर कैलाश, सीआर पार्क इलाके में रहने वाले लोगों की जाम की वजह से काफी समस्या हो रही है। इन इलाकों में कालोनियों के अंदर की सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। दोनों जगहों पर जाम से बचने के लिए यातायात पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्गों के उपयोग करने की सलाह दी गई है और वैकल्पिक मार्गों से संबंधित एडवाइजरी भी जारी की गई है।

जाम कम करने की दिशा में यातायात पुलिस की ओर से किए गए ये बदलाव

- दोनों तरफ के स्लिप रोड की चौड़ाई बढ़ाई गई। पहले एक स्लिप रोड 16 मीटर का था। दिल्ली से गुरुग्राम की ओर जाने वाले स्लिप रोड के किनारों पर मिट्टी डलवा कर व जर्सी बैरियर को पीछे कर ब्लैक सर्फेस बनवा दिया है। पहले 16 मीटर वाले स्लिप रोड को चौड़ा कर 19 मीटर कर दिया गया है।

- स्लिप रोड वाले मोड़ यानि हाइवे से उतर कर स्लिप रोड पर जाने वाला जो स्ट्रेच (मुड़ाव) है उसे चौड़ा किया गया। पहले ये मोड़ करीब 14 मीटर था, अब स्लिप रोड के दोनों लेन पर इसे 19-19 मीटर चौड़ा कर दिया गया है।

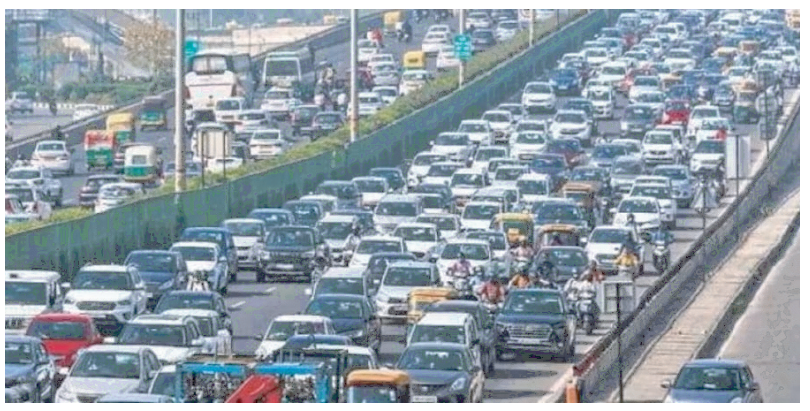

- रंगपुरी चौक पर महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे रात में अतिक्रमण हटाकर वहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए।

- महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे रंगपुरी चौक गोलचक्कर की दिल्ली से गुरुग्राम जाने आने वाली दोनों लाइनों को बंद कर दिया गया। सिर्फ वसंतकुज से एयरपोर्ट व एयरपोर्ट से वसंतकुंज जाने वाले मार्गों को खोला गया है।

- दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले सभी मार्गों के कट को बंद किया गया। एयरपोर्ट से ट्रैफिक को सीधे मेहराम नगर की तरफ निकाला गया। इससे ट्रैफिक सीधा चलता रहा।

- पुलिस ने इइवे पर कुछ यू-टर्न बनाए और कुछ बंद किए।

- दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाइवे पर दो शिफ्टों में तैनात होते थे। दो शिफ्टों को खत्म कर एक ही शिफ्ट कर दी गई है। पुलिसकर्मी सुबह सात से रात 11 बजे तक हाइवे पर ड्यूटी करेंगे।

- हाइवे पर कई क्रेन तैनात की गई हैं। ताकि खराब हुए वाहन को तुरंत हटाया जा सके।

- कुछ जगहों पर लाइटें लगाई गई हैं।

- वहीं, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे सारे यातायात सिग्नलों को मैनुअल कर दिया गया है।

- यातायात को सुचारू करने के लिए कुछ नए यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

- गूगल मैप से फ्लाईओवर के आसपास के इलाकों में यातायात की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

ये हैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे के लिए वैकल्पिक मार्ग

- दिल्ली से गुरुग्राम जाने व आने वाले यात्री महरौली-गुरुग्राम रूट लें।

- द्वारका, कापसहेड़ा और नजफगढ़ की ओर जाने को गुरुग्राम रोड फ्लाइओवर से पालम रोड होकर यात्रा करें।

- गुरुग्राम, कापसहेड़ा और द्वारका से धौला कुआं, वसंत विहार की ओर आने वाले यात्री द्वारका फ्लाइओवर रोड नंबर 201 लें।

चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के यात्री इन वैकल्पिक मार्गों का करें उपयोग

- धौला कुआं, एम्स, डिफेंस कालोनी आदि की ओर जाने को नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे से दाएं मुड़कर मूलचंद अस्पताल फ्लाईओवर की ओर लाला लाजपत राय मार्ग का प्रयोग करें।

- आइआइटी से नेहरू प्लेस की ओर जाने वाले रिंग रोड जाने को पंचशील फ्लाईओवर के नीचे से अगस्त क्रांति मार्ग पर बाएं मुड़ें। फिर मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे से लाला लाजपत राय मार्ग पर दाएं मुड़ें।

- आइआइटी से ग्रेटर कैलाश और नेहरू प्लेस की ओर जाने वाले आइआइटी फ्लाईओवर के नीचे से अरबिंदो मार्ग पर बाएं मुड़ कर रिंग रोड का प्रयोग करें। फिर मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे से लाला लाजपत राय मार्ग पर दाएं मुड़ें।

सांसों के संकट से राहत, विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे से 11वें स्थान पर खिसका गाजियाबाद

पी.वी न्यूज

गाजियाबाद में प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आइक्यू एआइआर की ओर से जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को देखें तो वर्ष 2022 में गाजियाबाद विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में 11वें स्थान पर रहा।

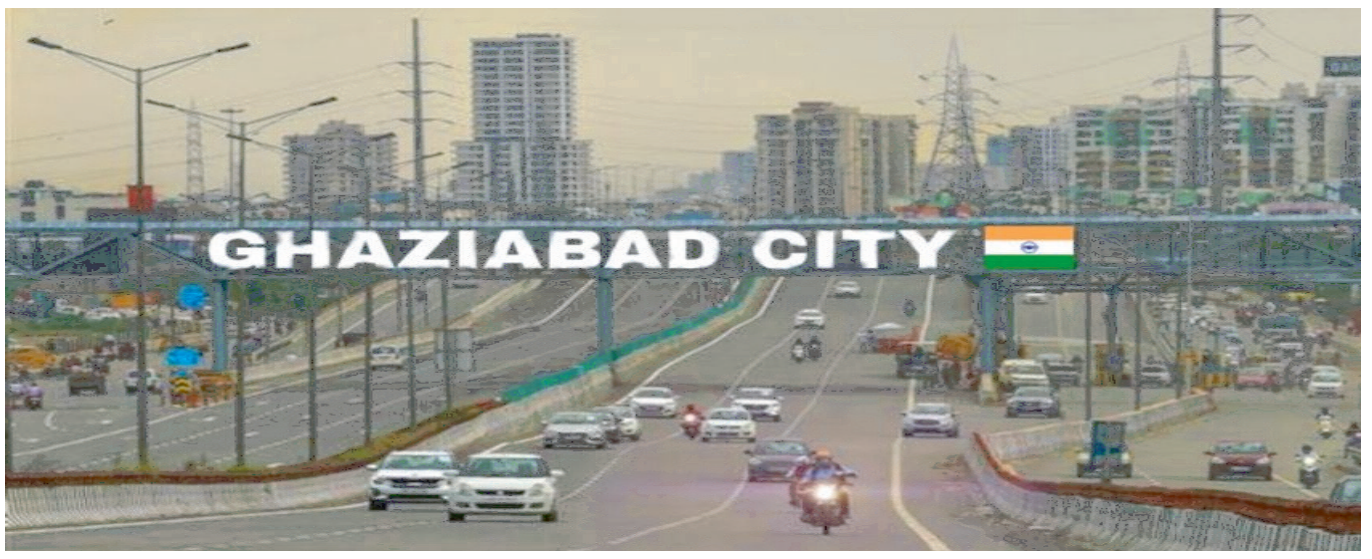

गाजियाबाद, । गाजियाबाद में प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आईक्यू एआईआर की ओर से जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को देखें तो वर्ष 2022 में गाजियाबाद विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में 11वें स्थान पर रहा। वर्ष 2020 और 2021 में गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में पीएम 2.5 पूरे साल का औसत 102 दर्ज किया गया था, जबकि वर्ष 2022 में पीएम 2.5 में 13.4 प्रतिशत की कमी के बाद 88.6 दर्ज किया गया।

आईक्यू एआईआर संस्था हवा में धुएं व धूल के हल्के कण (पीएम2.5) के आधार पर हर साल की रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो वर्ष 2018 से अब तक लगातार पीएम 2.5 में गिरावट आ रही है। इससे लोगों को राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा का कहना है कि जिले में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसका असर दिखना शुरू हो गया है।

पीएम 2.5 ही नहीं पीएम 10 (हवा में धूल के भारी कण) में कमी भी आई है।

धुएं का उत्सर्जन कम होने से राहत

उत्सव शर्मा ने बताया कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। सड़क से प्रदूषण करने वाले वाहन कम हुए हैं। ईस्टर्न पेरीफिरल एक्सप्रेस वे, एलीवेटेड रोड, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे समेत अन्य सड़कें बनने से जाम लगना कम हो गया है। इससे वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण होने वाला प्रदूषण कम हो गया है। इतना नहीं नहीं औद्योगिक इकाइयों का भी संचालन बिजली, सीएनजी या पीएनजी से हो रहा है। कूड़ा जलाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। उत्सव शर्मा का कहना है कि आगामी दो वर्ष में प्रदूषण के स्तर में और गिरावट दर्ज की गई है।

छह साल से लगातार पीएम में गिरावट

वर्ष	पीएम
2022	88.6
2021	102
2020	106.6
2019	110.2
2018	135.2

(पीएम2.5 का स्तर माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में है। आंकड़े पूरे वर्ष के औसत में हैं)

वर्ष 2022 में पीएम 2.5 के आधार पर तैयार AQI-

माह	AQI
जनवरी	135.5
फरवरी	104.4
मार्च	96.5
अप्रैल	87
मई	67.1
जून	54.9
जुलाई	32.1
अगस्त	29.5
सितंबर	38.5
अक्टूबर	103.1
नवंबर	157.3
दिसंबर	159.2

(आंकड़े पूरे माह के औसत में हैं)

AQI का मानक

0-50 - अच्छा
51- 100 - संतोषजनक
101 - 200 - मध्यम
201 - 300 - खराब
301 - 400 - बेहद खराब
401 - 500 - गंभीर

इनसाइड

मेडिकल रिपोर्ट में एनकाउंटर की कीमत 25 हजार रुपये, रिश्वत न देने पर फंसाने की धमकी

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर में विभाग कोई भी हो, रिश्वत का खेल बदस्तूर जारी है। एक ऐसा ऑडियो मिला है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस एनकाउंटर की कीमत 25 हजार रुपये आंकी गई है। दावा किया है कि ऑडियो बिसरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट का है। वह पुलिसकर्मियों से बात कर रहा है कि एनकाउंटर में घायल बदमाश की मेडिकल रिपोर्ट सही ढंग से तैयार करने के लिए डॉक्टर साहब को 25 हजार रुपये देने होंगे। 25 हजार नहीं देने पर मेडिकल रिपोर्ट बिगाड़ कर पुलिस टीम को फंसने की धमकी दी जा रही है। दरअसल, पुलिस एनकाउंटर के दौरान जब बदमाश को गोली लगती है तो उसको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां उसका मेडिकल होता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। मजिस्ट्रेट जांच में उस मेडिकल रिपोर्ट की भूमिका अहम होती है। मेडिकल रिपोर्ट में कई बार ब्लैकनिंग आ जाती है। ब्लैकनिंग उन मामलों में ही आती है जिनमें गोली करीब से लगी होती है। ब्लैकनिंग लिखने की धमकी देकर मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर 25 हजार की रिश्वत मांगने के मामले में स्वास्थ्य विभाग पर कई सवालिया निशान लगा दिए है। वहीं, बिसरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सचिंद्र मिश्रा ने बताया कि मामला दैनिक जागरण के माध्यम से संज्ञान में आया है।

बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक गिरफ्तार; साथी फरार

गाजियाबाद। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके में बुधवार देर रात लालबाग मार्ग मूवी मैजिक के सामने चैकिंग के दौरान पुलिस की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गिर गया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा जबकि साथी बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। गिरफ्तार घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया है।

सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि बुधवार रात को लोनी बॉर्डर पुलिस टीम लाल बाग मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार युवकों ने मोटरसाइकिल मोड़ भागने लगे। संदिग्ध लगने पर चैकिंग कर रही टीम ने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जो घायलावस्था में गिर गया और पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया। जबकि एक बदमाश भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर व 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस बरामद किया। जिसकी पहचान सलमान उर्फ़ टीपू पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी राजीव नगर हर्ष विहार दिल्ली के रूप में हुई।

सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के विभिन्न थानों में दो दर्जन मुकदमे गम्भीर धाराओं में दर्ज है। उन्होंने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार बदमाश को उपचार के लिये अस्पताल भेज दिया है और उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है। फरार साथी का नाम हरि उर्फ़ छोटू बताया है।

3 करोड़ रुपये उधार लेने के बाद खराब हुई नीयत, दोस्तों के साथ मिलकर 2 लोगों का किया मर्डर

ग्रेटर नोएडा। मेरठ जिला न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा के आक्सफोर्ड स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी व उनके दोस्त रामकिशोर की हत्या के मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर दो लाख बीस हजार का अर्थदंड लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में पांच अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया है।

केस की सुनवाई मेरठ जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद सिंह द्वितीय ने की। अधिवक्ता विनोद चौधरी ने बताया कि सिरसा स्थित आक्सफोर्ड स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी व उनके दोस्त रामकिशोर की सितंबर 2011 में सूरजपुर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप टीकम भाटी, जितेंद्र, सुभाष, कृष्ण, कविंद्र, प्रवीण, मनोज व सतेंद्र उर्फ सेठी पर लगा था।

सभी के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। सूरजपुर में रिपोर्ट इस वजह से दर्ज हुई, क्योंकि राजेश व रामकिशोर को सूरजपुर से ही बुलाया गया था। हत्या करने के बाद शव को घोड़ी बछेड़ा के समीप फेंक दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि राजेश ने टीकम को तीन करोड़ रुपये उधार दिए थे।

> मेरठ जिला न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा के स्कूल के प्रबंधक व उनके दोस्त की हत्या के मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जांच में तीन करोड़ रुपये उधार देने का मामला सामने आया।

टीकम की नीयत खराब हो गई और उसने उधार की रकम वापस करने के बजाय अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश व उसके दोस्त की हत्या कर दी। सुरक्षा कारणों से केस मेरठ जिला न्यायालय ट्रांसफर हुआ। सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह पेश हुए। गवाह एंव साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने टीकम भाटी, जितेंद्र व सुभाष को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

नाले की सफाई के दौरान मिले महिला के हाथ और पैर

अधिवक्ता विनोद ने बताया कि वह फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट जाएंगे। जिन लोगों को बरी किया गया है, उनकी भी घटना में भूमिका रही है। घटना में शामिल एक आरोपित की मौत हो चुकी है। नाबालिग होने की वजह से एक का बाल सुधार गृह में ट्रायल चल रहा है।

शादी के फर्जी दस्तावेज बनवाकर युवती ने मांगे 10 लाख रुपये, नहीं देने पर दी धमकी

मोदीनगर के एक व्यक्ति ने कौशांबी थाना क्षेत्र की एक युवती और उसके माता व पिता पर धोखाधड़ी व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है युवती ने शादी के फर्जी दस्तावेज बनवा लिए और उन्हें ब्लैकमेल कर दस लाख रुपये मांग रही है।

गाजियाबाद। मोदीनगर के एक व्यक्ति ने कौशांबी थाना क्षेत्र की एक युवती और उसके माता व पिता पर धोखाधड़ी व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है युवती ने शादी के फर्जी दस्तावेज बनवा लिए और उन्हें ब्लैकमेल कर दस लाख रुपये मांग रही है। रुपये नहीं देने पर फंसाने की धमकी दे रही है। पीड़ित ने कोर्ट की मदद से कौशांबी थाने में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानें पूरा मामला

मोदीनगर के एक व्यक्ति ने बताया उनका बेटा विदेश में नौकरी करता है। शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं। उनका आरोप है कि कौशांबी थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी की युवती ने ऑनलाइन उनके बेटे से बातचीत शुरू की। कुछ दिन बाद उनका बेटा घर लौटा। 17 मार्च 2022 को युवती ने बेटे को कॉल कर मिलने के लिए अपने घर बुलाया। बेटा घर लौटा तो वह काफी सहमा हुआ था।

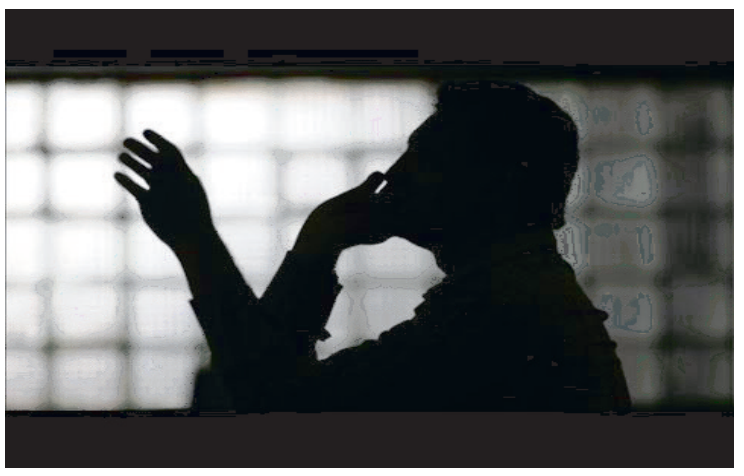

कुछ दिन बाद युवती ने उनके मोबाइल नंबर पर उनके बेटे से शादी का प्रमाण पत्र भेजा। उसपर बेटे के हस्ताक्षर नहीं थे। उन्होंने बेटे से जानकारी कि तो उसने बताया कि युवती उनसे पहले ही तीन लाख रुपये ठग चुकी है। होली पर उसने माता और पिता की मौजूदगी में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। इससे उनकी हालत खराब हो गई थी। अब युवती उन्हें ब्लैकमेल कर दस लाख रुपये मांग रही है।

रुपये नहीं देने पर झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस से गुहार लगाई और एसएसपी से भी मिले। कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कूड़ा बीनने वाले दोस्तों में विवाद, एक ने शराब की बोतल से वार कर ली दूसरे की जान; नाले में फेंका शव

कूड़ा बीनने को लेकर हुए विवाद के बाद दो दोस्तों ने साथ में शराब पी और इसी दौरान दोबारा कहासुनी होने के बाद एक ने शराब की बोतल तोड़कर वार कर दूसरे की हत्या कर दी। शव को नाले में फेंक दिया।

गाजियाबाद। कूड़ा बीनने को लेकर हुए विवाद के बाद दो दोस्तों ने साथ में शराब पी और इसी दौरान दोबारा कहासुनी होने के बाद एक ने शराब की बोतल तोड़कर वार कर दूसरे की हत्या कर दी। शव को नाले में फेंक दिया। झगड़ा जीटी रोड पर हुआ और शव आप्युलेंट मॉल के पास नाले से बरामद हुआ था। अज्ञात शव मिलने के बाद छानबीन कर पुलिस ने मंगलवार को हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया।

सीसीटीवी कैमरे से हुई पहचान

मामले को लेकर एसीपी नंदग्राम आलोक दुबे ने बताया कि छह मार्च की सुबह नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पहचान विजयनगर के इमरान के रूप हुई, जो अपने छोटे भाई के परिवार के साथ रहकर कूड़ा बीनता था। शव पर चोट के कई निशान मिले हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई थी। शव मिलने वाले स्थान के आसपास दो-दो किमी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो जीटी रोड पर ही देसी शराब के एक ठेके के पास दो व्यक्ति झगड़ते मिले।

कूड़े के बैग में रखकर नाले में फेंका शव

स्वजन ने हमला करने वाले की पहचान बिहार में मधुबनी के संजीव उर्फ सुमित के रूप में की। संजीव नासिरपुर में रहता है। आरोपित को पुलिस ने सोमवार सुबह गुलमोहर एनक्लेव के पास से गिरफ्तार कर लिया। संजीव ने बताया कि वह इमरान के साथ कूड़ा बीनता था। इमरान अकसर उसके हिस्से का कूड़ा उठा लेता था। इसको लेकर पूर्व में झगड़ा भी हुआ। पांच मार्च की रात को दोनों शराब पी रहे थे। इसी दौरान उसने इमरान से कूड़े को लेकर बात की, जिस पर वह गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद उसने शराब की खाली बोतल तोड़कर इमरान के सिर, गर्दन और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए और शव को कूड़े के बैग में रखकर नाले में फेंक दिया। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

सिर्फ 19 प्रतिशत रह गई थी हृदय की कार्यगति, यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में हुआ दुर्लभ प्रोसिजर

मरीज के लिए यह प्रोसिजर अत्यन्त जरूरी एवं जीवन रक्षक था इसलिए उसने प्रोसिजर कराने का निर्णय लिया और 28 फरवरी 2023 को यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। चूंकि मरीज का हृदय काफी कमजोर था।

गाजियाबाद। कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में हृदय रोग के उपचार के लिए एक दुर्लभ प्रोसिजर को सफलतापूर्वक किया गया। श्याम पार्क एक्सटेंशन, साहिबाबाद निवासी 65 वर्षीय मरीज का एओर्टिक वॉल्व सिकुड़ गया था, जिसकी वजह से उनकी सांस काफी फूलती थी और छाती में हमेशा भारीपन रहता था। विभिन्न अस्पतालों में एवं डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनको कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि उनके हृदय की कार्यगति केवल 19 प्रतिशत रह गयी थी, जिसकी वजह से कोई भी अस्पताल उनका प्रोसिजर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। काफी जगह भटकने के बाद उन्हें यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के बारे में पता चला और उन्होंने हृदय रोग टीम के विशेषज्ञ डॉ. असित खन्ना और डॉ. आयुष गोयल से परामर्श किया।

ओपन हार्ट सर्जरी के वैकल्पिक प्रक्रिया से हुआ प्रोसिजर

परामर्श के पश्चात यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की हृदय रोग टीम ने इस प्रोसिजर को एक ओपन हार्ट सर्जरी के वैकल्पिक प्रक्रिया ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिपलेस्मेन्ट विधि द्वारा करने की सहमति प्रदान की। चूंकि यह प्रोसिजर काफी मंहगा है इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल प्रबन्धन एवं वॉल्व बनाने वाली कम्पनी से बात कर मरीज को काफी रियायत दिलायी।

मरीज के लिए यह प्रोसिजर अत्यन्त जरूरी एवं जीवन रक्षक था, इसलिए उसने प्रोसिजर कराने का निर्णय लिया और 28 फरवरी 2023 को यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। चूंकि मरीज का हृदय काफी कमजोर था, इसलिए पूरी तैयारी के साथ प्रोसिजर को 6 मार्च 2023 को डॉक्टरों की टीम ने जांघ के रास्ते से तार से छतरीनुमा उपकरण को खराब वॉल्व के स्थान पर सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया।

महज डेढ़ घण्टे में हुआ प्रोसिजर

इस प्रोसिजर में किसी भी तरह की बड़ी चीर-फाड़ नहीं की गई और ओपन हार्ट सर्जरी की अपेक्षा मात्र डेढ़ घण्टे में इस प्रोसिजर को कर दिया गया। इसमे मरीज को बेहोश भी नही किया गया, जबकि ओपन हार्ट सर्जरी में सात से आठ घण्टे लगते हैं और पूरे समय मरीज को बेहोश रखा जाता है।

डॉक्टरों की टीम में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. असित खन्ना, डॉ. धीरेन्द्र सिंघानिया, कन्सलटेन्ट हृदय रोग एवं ऐओर्टिक सर्जन डॉ. आयुष गोयल तथा कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉ. गौरव कनवर शामिल थे। डॉ. असित खन्ना ने बताया की प्रोसिजर के दूसरे दिन ही मरीज चलने-फिरने लगा था और 9 मार्च 2023 को मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी गयी। छुट्टी के पश्चात भी फोन द्वारा मरीज की शारीरिक स्थिति की पूर्ण जानकारी यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के द्वारा अपडेट की जाती रही और छुट्टी के चौथे दिन जब मरीज ओ.पी.डी. में फोलोअप के लिए आया तो उसके हृदय की कार्यक्षमता 50 प्रतिशत पायी गयी।

मरीज अब अपनी सामान्य दिनचर्या और आराम से जीवन यापन कर पा रहा है। डॉ. आयुष गोयल ने बताया कि इस प्रोसिजर में हार्ट या चेस्ट कैविटी को खोलने की जरूरत नहीं होती और जिस तरह से कॉर्डियक स्टेन्ट लगाया जाता है उसी प्रकार वॉल्व का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इससे पूर्व भी सफल TAVI प्रोसिजर एवं जटिल हृदय रोग ऑपरेशन किया जा चुके हैं। भारत में अभी तक कुछ अस्पतालों में ही इस प्रकार की सुविधा होने के कारण, कुछ ही हजार TAVI प्रोसिजर्स किये गये हैं।

इनसाइड

Honda CB500F बाइक की दिखी पहली झलक, जल्द लॉन्च होने की उम्मीद, जानें किन फीचर्स से हो सकती है लैस

Honda CB500F Bike जल्द ही भारतीय ऑटो बाजार में देखने को मिल सकती है। इसे होंडा के एक डीलरशिप में देखा गया है। बता दें कि इसे ब्रांड के 500cc सेगमेंट में लाने की बात कही जा रही है और कई नए फीचर्स को देखा जा सकेगा।

नई दिल्ली। दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा जल्द ही अपनी एक नई बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में बेंगलुरु के एक होंडा डीलरशिप पर नई Honda CB500F बाइक को देखा गया है। कुछ समय पहले होंडा ने भारत में अपने नए 500cc प्लेटफॉर्म के आधार पर एक बाइक को लॉन्च करने की बात कही थी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में यह वही बाइक है, जिसके बारे में होंडा ने बात की थी।

मिल सकता है जबरदस्त पावरट्रेन

नई होंडा CB500F को नेकेड बाइक सेगमेंट में एक माइल्ड इंजन के साथ लाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, इस बाइक में 471cc वाला पैरेलल ट्विन मोटर दिया जा सकता है, जो 600rpm पर 47.5PS की पावर और 6500rpm पर 43Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा।

ट्रांसमिशन के लिए बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स को भी जोड़ा जा सकता है। बता दें कि बिगविंग के लिए अपने 500cc पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए होंडा काफी समय से काम कर रही है। इस कारण होंडा की इस बाइक को लाये जाने की बात कही जा रही है।

बेहतर राइडिंग का मिलेगा अनुभव

नई होंडा बाइक को बेहतर राइडिंग का अनुभव देने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। इसमें 41mm के फ्रंट फोर्क और दोनों सिरों पर प्री-लोड-एडजस्टेबिलिटी के साथ एक रियर प्रो-लिंक मोनोशॉक शामिल किए जा सकते हैं। वहीं, ब्रेकिंग के लिए फ्रंट व्हील पर 320mm का डिस्क ब्रेक और 240mm रियर डिस्क देखने को मिल सकता है। इसके आलवा, डुअल-चैनल ABS ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए जोड़ा जा सकता है।

Honda CB500F की कीमत और लॉन्चिंग

Honda CB500F बाइक को भारत में अगले साल जून तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 4.79 लाख रुपये है। वहीं, लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Benelli Leoncino 500 बाइक से होगा।

नई Royal Enfield Super Meteor 650 से उठा पर्दा, जानें क्या हैं रेट्रो लुक वाली इस क्रूजर बाइक के फीचर्स

नई दिल्ली, । रॉयल एनफील्ड ने काफी लंबे समय से इंतजार की जा रही अपनी सुपर मीटियोर 650 (Super Meteor 650) बाइक से पर्दा उठा दिया है। इसे इटली में आयोजित 2022 EICMA शो में पेश किया गया है और उम्मीद है कि इसे इसी महीने भारत में होने वाली राइडर मेनिया इवेंट 2022 में भी शोकेस किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि पेश हुई रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 एक क्रूजर बाइक है, जिसे रेट्रो लुक में उतारा गया है। इसके अलावा, इसमें 648cc वाले पैरेलल-ट्विन इंजन भी दिया गया है। इवेंट में सामने आई बाइक एक एक लो-प्रोफाइल बाइक है, जो काफी हद तक मीटियोर 650 की तरह ही दिखती है, लेकिन इसमें कई प्रीमियम एलीमेंट्स को शामिल किया गया है। इसे टूरर ट्रिम में एक लंबी विंडस्क्रीन, एक पिलर बैकरेस्ट, ड्यूल सीट्स, पैनियर, एक टूरिंग हैंडलबार और बड़े फुटपेग जैसे कई बिट्स मिलते हैं। साथ ही बाइक में 1,500mm का लंबा व्हीलबेस देखने को मिलता है।

Honda CB500F Bike Seen In

एम जी हेक्टर : अब करीब करना होगा दो महीने का इंतजार, घटा वेटिंग पीरियड

एमजी हेक्टर वेटिंग पीरियड एमजी मोटर इंडिया ने इस साल जनवरी में नई एमजी हेक्टर को लॉन्च किया था। वहीं इस कार के लिए आपको करीब दो महीने का इंतजार करना होगा। चलिए आपको इस कार से जुड़ी खास बातें बताते हैं।

एमजी हेक्टर इंडिया ने इस साल जनवरी में नई एमजी हेक्टर को लॉन्च किया था। अगर आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको बता दें वाहन निर्माता कंपनी ने इसके लिए वेटिंग पीरियड की अवधि को कम कर दिया है। हेक्टर को बुक करने वाले इच्छुक ग्राहक को इस कार के लिए करीब दो महीने का इंतजार करना होगा। चलिए आपको इस कार से जुड़ी खास बातें बताते हैं।

एमजी हेक्टर के लिए वेटिंग पीरियड क्या है?

जैसा की आपको हम बता चुके हैं कि इस कार के लिए आपको दो महीने का इंतजार करना होगा। वहीं स्मार्ट ईएक्स ट्रिम खरीदने वाले लोगों को लंबा इंतजार करना होगा। स्मार्ट ईएक्स के लिए पूरे भारत में चार महीने का वेटिंग पीरियड है। जबकि टॉप-स्पेक सैवी प्रो में केवल एक महीने की सबसे कम वेटिंग पीरियड के साथ आती है।

एमजी हेक्टर वेरिएंट

2023 के अपडेट के साथ, एमजी हेक्टर को दो नए वेरिएंट मिलते हैं और अब ये कुल 6 वेरिएंट में आती है, ये स्टाइल, शाइन, स्मार्ट, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो और सेवी प्रो में आती है। एडीएएस की विशेषताएं टॉप, सैवी प्रो वेरिएंट तक सीमित है।

डिजाइन

आपको बता दें, इस फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है, इसमें बड़े पैमाने पर डायमंड-स्टडेड पैटर्न क्रोम ग्रिल, जो MG का कहना है कि स्कॉटलैंड में प्रसिद्ध Argyle डिज़ाइन पैटर्न से प्रेरित है। इसके अलावा इसमें फ्रंट और रियर बंपर, स्प्लिट एलईडी हेडलैंप, एलईडी टेल लैंप, हेक्टर बैजिंग और बूट लिड की लंबाई पर चलने वाला रिफ्लेक्टर भी होता है। इसमें 18 इंच का अलॉय व्हील भी मिलता है।

कीमत में हुई बढ़ोतरी

भारतीय बाजार मे पिछले महीने, एमजी इंडिया ने घोषणा की कि वह 1 मार्च, 2023 से अपने मॉडलों में कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा इसके चुनिंदा वेरिएंट अब 36 हजार रुपये महंगी है।

मार्केट में छा जाने की तैयारी में बीएमडबल्यू, आ रही हैं तीन शानदार गाड़ियां

बीएमडबल्यू भारत में अपने तीन मॉडल्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन्हें मई और अगस्त में लॉन्च होने की बात कही जा रही है। तो चलिए इन मॉडल्स के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडबल्यू (BMW) भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत आने वाले महीने में कंपनी अपने तीन नए मॉडल पेश करने वाली है। इसमें दूसरी पीढ़ी के बीएमडब्ल्यू एम2 (BMW M2), जेड4 फेसलिफ्ट और बीएमडब्ल्यू एक्स5 (BMW X5) मॉडल शामिल हैं। इन सभी मॉडल्स को मई से अगस्त के बीच आने की उम्मीद है। तो चलिए बीएमडबल्यू की इन अपकमिंग कार्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

BMW M2

बीते साल अक्टूबर महीने में पेश की गई 2023 BMW M2 कार को इस साल मई में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आगामी बीएमडब्ल्यू एम2 पूरी तरह से इंपोर्टेड कार होगी, जिसमें ब्रांड की S58 पावर यूनिट को शामिल किया जा रहा है। M2 में 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो चार्ज्ड इनलाइन-6 सिलेंडर इंजन को थोड़ा डी-ट्यून किया गया है, जो 453bhp की पावर और 550Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है।

यह कार 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन से जुड़ा होगा, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है। मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह कार 24.1 सेकंड में 0-60 मील प्रति घंटे की सपोईड तक पहुंच सकती है, जबकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ इसे 3.9 सेकंड का समय लगता है। अनुमान है कि BMW M2 कार को भारत में एक करोड़ रुपये की कीमत पर उतारा जा सकता है।

2023 BMW Z4 Facelift

कंपनी सिंगल वेरिएंट के साथ अपने Z4 फेसलिफ्ट मॉडल को भी लॉन्च करने वाली है। भारत में इसका M40i वर्जन लाए जाने वाला है। पावरट्रेन के रूप में इस कार में कार में 3.0L इनलाइन-सिक्स इंजन दिया गया है, जो 382bhp की पावर और 500Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह एक फीचर फुल कार होगी, इस वजह से इसमें म स्पोर्ट डिफरेंशियल, एम स्पोर्ट ब्रेक पैकेज, ब्रेकिंग के साथ क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लाउडस्पीकर ऑडियो जैसे बहुत-से फीचर्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि भारत में इसे करीब 90 लाख रुपए में लॉन्च किया जा सकता है।

2023 BMW X5 Facelift

BMW X5 की फेसलिफ्ट कार को अगस्त, 2023 में लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं, अप्रैल 2023 तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। बीएमडब्ल्यू के मुताबिक, इस कार में हेडलाइट्स पहले की तुलना में 35 मिमी एमएम नैरो हो गई हैं। वहीं, कलर ऑप्शन में X5 में ब्रुकलिन ग्रे, आइल ऑफ मैन ग्रीन और मरीना बे ब्लू को शामिल किया गया है। बीएमडब्ल्यू के आईड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम में लेटेस्ट 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 14.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। साथ ही क्लाउड-आधारित बीएमडब्ल्यू मैप्स नेविगेशन शामिल है।

Hyundai i10 Facelift से उठा पर्दा, ADAS फीचर और तीन इंजन विकल्प के साथ मिला है शानदार लुक

हुंडई की नई i10 कार को ग्लोबल लेवल पर पेश कर दिया गया है। यह एक फेसलिफ्ट कार है जिसमें ADAS जैसे लेटेस्ट फीचर को शामिल किया गया है। वहीं इस कार में तीन इंजन का विकल्प मिलता है।

नई दिल्ली। हुंडई मोटर एक के बाद एक अपने नए मॉडल्स को पेश कर रही है। अभी कुछ समय पहले ही वाहन निर्माता ने भारत में अपने ग्रैंड i10 नियोस (Grand i10 Nios) मॉडल को लॉन्च किया था, अब कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर 2023 हुंडई i10 को पेश कर दिया है। 2023 Hyundai i10 मौजूदा मॉडल या भारत में बेचे जाने वाले मॉडल की तुलना में थोड़े अपडेट्स के साथ आई है। N-लाइन वर्जन में आई ये Hyundai कार N परफॉर्मेंस डिवीजन से प्रेरित डिजाइन के साथ आई है।

2023 Hyundai i10 का लुक

लुक और डिजाइन के मामले में हुंडई i10 में ग्रिल पर हनीकॉम्ब के आकार के डीआरएल को रखा गया है। लाइटिंग के लिए इस कार में ट्वीक एलईडी लाइट को शामिल किया गया है, जो सिग्नेचर फ्रंट रिफ्लेक्टर हेडलैंप और ललाइट्स के लिए नए एलईडी ग्राफिक्स के साथ आते हैं। बम्पर पर एक नया पैटर्न दिया गया है और 15 इंच के अलॉय व्हील्स इसके लुक को और बढ़ा देते हैं। कार में खास डिजाइन के साथ 16 इंच के रिम्स भी हैं। मॉडल को नौ बाहरी रंगों के साथ उपलब्ध कराया गया है, जिनमें दो सिटी कार, लुमेन ग्रे और मेटा ब्लू जैसे नए रंग भी हैं। ग्राहक चाहें तो विकल्प के रूप में ब्लैक रूफ भी रख सकते हैं।

मिलता है दो इंजनों का विकल्प

Hyundai i10 को तीन इंजनों के विकल्प के साथ लाया गया है। इसमें पहला विकल्प 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जबकि दूसरा विकल्प 1.2-लीटर चार-सिलेंडर इंजन है। इसका तीसरा विकल्प टर्बोचार्ज्ड 1.0 TGD-i इंजन है। 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 66 hp की पावर के साथ आता है। वहीं, 1.2-लीटर चार-सिलेंडर इंजन 83 hp पावर और टर्बोचार्ज इंजन 99 hp की पावर जनरेट करने में सक्षम है।

कई लेटेस्ट फीचर्स से लैस है नई i10

नई 2023 i10 कार के केबिन में बैंगनी रेखाओं के साथ टार्टन फैब्रिक सीटें और नई नीली एम्बिएंट लाइट देखने को मिलती है। वहीं, फीचर्स लिस्ट में 4.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट मिलता है। साथ ही रियरव्यू कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट और रियर USB-C पोर्ट भी है। ध्यान देने वाली बात है कि कार को ADAS हुंडई स्मार्ट सेंस के साथ ADAS पैकेज भी मिलता है।

मिड डे मील में शामिल हो मोटा अनाज

अदित कंसल

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स (मोटा अनाज) वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। पूरी दुनिया में भारत सर्वाधिक मोटा अनाज पैदा करने वाला देश है। विश्व में मोटा अनाज उत्पादन का लगभग 41 प्रतिशत भारत में पैदा होता है।

स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के मुताबिक हिमाचल की आधी आबादी कुपोषण का शिकार है। प्रदेश का हर तीसरा मरीज मधुमेह पीड़ित है। भारत में सबसे अधिक टीबी के मामले हिमाचल में सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एनीमिया मुक्त हिमाचल के लिए अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार ने मिड-डे-मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया है। बेहतर होगा कि नाम के साथ-साथ मिड-डे-मील की थाली का स्वरूप भी बदला जाए। बच्चों को चावल के साथ मोटे अनाज भी परोसे जाने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की सार्थकता तभी है, जब हम ऐसा करेंगे'

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स (मोटा अनाज) वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। पूरी दुनिया में भारत सर्वाधिक मोटा अनाज पैदा करने वाला देश है। विश्व में मोटा अनाज उत्पादन का लगभग 41 प्रतिशत भारत में पैदा होता है। मोटे अनाज हमारी संस्कृति व सभ्यता का हिस्सा होने के साथ-साथ सस्ते और पोषण से भरपूर हैं। मोटे अनाज एनर्जी बार हैं तथा पोषण का पावर हाउस हैं। ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, रागी, मंडवा, मक्का, चीना, कुट्टू और चौलाई जैसे मोटे अनाज यानी मिलेट्स आधुनिक सुपर फूड हैं। सरकार ने 2023-24 के बजट में मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु अलग से एक योजना की शुरुआत की है जिसे 'श्री अन्न योजना' का नाम दिया गया है। इस योजना के माध्यम से देश में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों में वृद्धि करने और कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु 15 अगस्त 1995 को मिड-डे-मील योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को विशेष उद्देश्य से आरंभ किया गया था। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते।

दोपहर का भोजन बच्चों की कुपोषण की समस्या दूर करता है तथा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका अदा करता है। यदि हम हिमाचल की बात करें तो प्रदेश के 10732 प्राइमरी स्कूलों के 306639 विद्यार्थियों और अपर प्राइमरी के 4783 स्कूलों के 212850 विद्यार्थियों को मिड-डे-मील दिया जाता है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के 51000 बच्चों को भी मिड-डे-मील सुविधा प्रदत है। अगर हम विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का आकलन करें तो

प्रदेश में 26 फीसदी बच्चों का कद औसत से कम है, यानी बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। वहीं आईजीएमसी शिमला के कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी विभाग में दिल की सर्जरी के लिए आने वालों में बच्चे ज्यादा हैं। बहुत से बच्चों के दिल में छेद पाए जा रहे हैं। कई बच्चे एनीमियाग्रस्त हैं। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी अवसाद का शिकार हैं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के मुताबिक हिमाचल की आधी आबादी कुपोषण का शिकार है। प्रदेश का हर तीसरा मरीज मधुमेह पीड़ित है। भारत में सबसे अधिक टीबी के मामले हिमाचल में सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एनीमिया मुक्त हिमाचल के लिए अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार ने मिड-डे-मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया है। बेहतर होगा कि नाम के साथ-साथ मिड-डे-मील की थाली का स्वरूप भी बदला जाए। बच्चों को रोज चावल ही दिए जाते हैं, यानी बच्चों की थाली मोटे अनाज से खाली है।

अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 तभी सार्थक होगा जब हम बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में पोषण से भरपूर मोटा अनाज दें। आज देश के पांच सितारा होटलों में मोटे अनाज का प्रयोग सब्जियों एवं सलाद में हो रहा है। विद्यार्थियों को बाल्यवस्था से ही मोटे अनाज से रूबरू करवा देना चाहिए। बाजरे की रोटी, खिचड़ी, दलिया, भुना बाजरा थाली में परोसा जा सकता है। बाजरा आयरन का सबसे सस्ता स्त्रोत है। इससे विद्यार्थी एनीमिया मुक्त हो सकेंगे क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। इसी प्रकार ज्वार व रागी की ब्रेड, बिस्कुट व केक भी थाली की शोभा बढ़ा सकते हैं। मोटे अनाज में ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम होती है तथा रेशेदार होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसलिए मोटे अनाज उच्च शर्करा, मोटापे, पाचन समस्याओं, एनीमिया, शारीरिक कमजोरी को दूर करते हैं। हाल ही में बल्लभ महाविद्यालय मंडी की सहायक प्रोफेसर डा. तारा देवी सेन ठाकुर ने हिमाचली जड़ी-बूटियों से बनने वाले पास्ता की खोज की है। इस पास्ता में गिलोय पाउडर के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्यवर्धक जड़ी-बूटियों का प्रयोग किया गया है तथा इसमें कृत्रिम परिरक्षक भी नहीं हैं। निःसंदेह यह औषधीय गुणों से भरपूर पास्ता विद्यार्थियों को अनेक बीमारियों से दूर रखेगा तथा वे बाजार में मिलने वाले हानिकारक फास्ट फूड के चक्रव्यूह से भी निश्चित रूप से बाहर निकल पाएंगे।

इस पास्ते को भी थाली का हिस्सा बना दिया जाए तो लाखों बच्चे लाभान्वित होंगे तथा मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल, तेज बुखार, पेट खराब और कैंसर जैसी घातक बीमारियों में लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर हिमाचली खोज को धरातल व सम्मान मिलेगा। सेवानिवृत्त भू-संरक्षण अधिकारी यादव किशोर गौतम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोणी (कंगनी), बाथू (चौलाई), कोदा जैसे मोटे अनाजों की खेती आज भी की जाती है। सरकार द्वारा बीजों की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषकों को मोटे अनाज की खेती पर अधिक ध्यान व रुचि लेनी चाहिए क्योंकि इसमें शस्य क्रियाएं कम हैं तथा यह शुष्क व कम उपजाऊ भूमि पर भी हो जाते हैं। अंत में हमें स्वीकार करना होगा कि जब तक मोटे अनाज (मिलेट्स) हमारी थाली का हिस्सा नहीं बनते, तब तक अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज (मिलेट्स) वर्ष बेमानी है।

संपादक की कलम से

संविधान के सामने समलैंगिकता

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने एक मानवीय, लैंगिक, प्राकृतिक संबंधों की व्याख्या का मामला है। एक दर्जन से अधिक याचिकाएं विचाराधीन हैं, जिनमें समलैंगिक संबंधों को 'कानूनी मान्यता' देने के आग्रह निहित हैं। भारत सरकार ने अपने 56 पृष्ठीय हलफनामे में समलैंगिकता और ऐसे विवाह का विरोध किया है। इस मुद्दे को संसद के अधिकार-क्षेत्र में ही रहने की दलील भी दी गई है। संसद इन संबंधों की सामाजिकता, निजता, स्वाभाविकता और नैसर्गिकता पर व्यापक विमर्श करेगी और फिर कानून पारित करेगी। सरकार अदालती पीठ और इस मुद्दे की सुनवाई को संसद के अधिकार-क्षेत्र में दखल का प्रयास मान रही है। दरअसल भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विवाह एक पवित्र संस्कार है, विपरीत लिंग के स्त्री-पुरुष का सामाजिक-मानसिक गठबंधन है तथा संतानोत्पत्ति के जरिए इस दुनिया को निरंतर बनाए रखने की सोच और कोशिश है। विकृत्तियां कई स्तर पर हो सकती हैं। ये शारीरिक, दिमागी, गर्भस्थ आदि हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जिस व्यवस्था को समाज और कानून में मान्यता प्राप्त है, उसका उल्लंघन क्यों किया जाए? ऐसा अतिक्रमण क्यों जरूरी है, जो प्राकृतिक भी नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने 6 सितंबर, 2018 को एक महत्वपूर्ण, लगभग ऐतिहासिक, फैसले में धारा 377 (1) को 'गैर आपराधिक' घोषित किया था, जिसमें समलैंगिक संबंधों को 'अप्राकृतिक अपराध' कहा गया था। जिस एलजीबीटी समुदाय ने उस फैसले को अपनी निजता, कामेच्छा, स्वाभाविकता की ऐतिहासिक जीत करार दिया था, उसमें महिला-महिला संबंध, पुरुष-पुरुष संबंध, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, द्विलिंगी, एसेक्सुअल आदि मनोवृत्तियों के लोग, समुदाय आते हैं। इन लोगों में विपरीत लिंगी के सामाजिक आदर्शों की अनुपस्थिति होती है। भारत में यह सामाजिक समूह विशिष्ट है, जिसमें 'हिजड़ा' भी शामिल हैं। उन्हें 'थर्ड जेंडर' भी कहा जाता है। दरअसल अब प्राचीन ग्रंथों, पुराण आदि के कुछ दुर्लभ उदाहरण देकर तार्किक मांग की जा रही है कि समलैंगिक संबंधों को भी कानूनी मान्यता दी जाए, ताकि उनके प्रति समाज, कार्यस्थल, रोज़ाना की ज़िन्दगी में 'असामाजिक' और 'घृणित' न समझा जाए। 'भगवद पुराण' में ऐसा उल्लेख बताया जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को मोहिनी के अवतार में देखा और उनके मिलन के फलस्वरूप भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। शिखंडिनी और बृहन्नाला के प्रसिद्ध पात्र 'महाभारत' के सबसे सम्मानित ट्रांसजेंडर पात्र हैं। 'वाल्मीकि रामायण' में भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा भगीरथ का जन्म उनकी दो माताओं और राजा दिलीप की विधवाओं के मिलन से हुआ था। दरअसल ये मिथकीय कहानियां हैं, आम आदमी के पास वे अलौकिक और दैवीय शक्तियां नहीं हैं, लिहाजा इनके उदाहरण भी बेमानी हैं। भारत में संविधान को ग्रहण करने के बाद भी समलैंगिक संबंधों को 'आपराधिक कृत्य' माना गया था। भारत में विवाह को एक पवित्र संस्थान का दर्जा प्राप्त है और स्त्री-पुरुष मिलन को ही वैधता, सामाजिकता और एक पारिवारिक ईकाई के तौर पर स्वीकृति है। हमारी दलील कुछ अजीब-सी लग सकती है, लेकिन यह ब्रह्म-सत्य है कि पशु और जानवर में भी विपरीत लिंग के प्रति प्राकृतिक आकर्षण होता है। उनमें समलैंगिक संबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति है। बहरहाल याचिकाएं सर्वोच्च अदालत में हैं।

मेष : आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आप सभी को जोड़ने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिसमें आप कामयाब अवश्य होंगे और मित्रों के साथ आप मनोरंजन के कार्यक्रम में जा सकते हैं।

वृष : आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा, इसलिए आप संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यदि उन्हें कोई भी समस्या चल रही है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और अपने कामों की सूची बनाएं, तभी आगे बढ़े और आपके सभी काम पूरे हो सकेंगे।

मिथुन: आज के दिन साझेदारी में व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए कुछ कमजोर रहने वाला है। परिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके जरूरी कार्यों में आप सावधानी बरतें।

कर्क : आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा रहने वाला है। आप कार्यक्षेत्र के कामों को लेकर पूरी मेहनत और ईमानदारी दिखाएंगे, तभी आप तरक्की कर सकेंगे।

सिंह : आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपको परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे, तो वह उस पर खरी उतरेगी।

कन्या : आज के दिन आपको शीघ्रता और भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। माता-पिता को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य से आप यदि कुछ धन उधार मांगे, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा।

तुला : आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सबको हैरान करेंगे, जिससे आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।

वृश्चिक: आज का दिन आपके चारों ओर का वातावरण सुखमय रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग काम के बोझ को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं।

धनु: आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए कमजोर रहने वाला है, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी योजनाओं से मन मुताबिक लाभ ना मिलने से उन्हें थोड़ी निराशा होगी। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नये मेहमान की दस्तक हो सकती है।

मकर: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आपको व्यवसाय के कुछ कामों को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी और आप घर बाहर दोनों जगह संतुलन बनाकर रखें, नहीं तो परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं।

कुंभ: आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। शासन सत्ता का पूरा लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन आप अपने खर्चों के साथ-साथ आज कुछ बचत की योजनाओं पर भी ध्यान लगाएं, तभी आप अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएंगे।

मीन : आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्य लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आने वाला है, उन्हें आज कोई अच्छा लाभ मिल सकता है।

अध्यापकों से गैर शिक्षण कार्य क्यों?

डा. वरिंदर भाटिया

आज विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर के निम्न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण शिक्षक द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे रहना ही है। आज शिक्षक अन्य कार्यों के भार तले दब गया है तथा इनके पूर्ण न हो पाने पर कार्रवाई के डर के कारण वह अपने मूल कार्य से दूर ही रहता है। अतः अब वह समय आ गया है कि शिक्षक को केवल शिक्षण और शिक्षा से जुड़े कार्य करने दिए जाएं तथा अन्य कार्यों हेतु कोई और व्यवस्था कर ली जाए। अन्यथा एक दिन हम बहुत पिछड़ जाएंगे और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा'

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री ने गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य न लेने के मद्देनजर और छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए पुरानी प्रथा को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यह जरूरी है कि शिक्षक हमेशा स्कूलों में उपलब्ध रहें और उनसे पढ़ाने के अलावा कोई अतिरिक्त काम न लिया जाए। बात सिर्फ पंजाब तक नहीं सीमित है, देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य लेने की रिवायत ही चलती है जिससे सब जगह स्कूल शिक्षा बुरी तरह प्रभावित होती है। प्रशासनिक व्यवस्था शिक्षक को सब काम करने वाला सर्वगुण युक्त निःसहाय प्राणी समझ लेती है जिससे आज हमारे अनेक शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझकर रह गए हैं। अनेक स्थानों पर उनसे स्टाफ की कमी के कारण दफ्तरी काम भी लिए जाते हैं। कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग हो या विद्यार्थियों की फोटो अपलोड व सत्यापन, दिनभर में ऐसे ही जाने कितने कार्य शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा करने पड़ते हैं। इनसे कहीं क्लर्क जैसा काम करते गलती हो जाए तो जॉब पर आफत बन आती है। इस पर तुरंत प्रभाव से हमें सोचना होगा।

मिड डे मील की पूरी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक की ही होती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से बच्चों को दिए जाने वाली अनेक सुविधाएं जैसे स्कूल यूनिफार्म, जूते, मोजे, बैग, पुस्तकें इत्यादि की खरीद-फरोख्त एवं बांटने की जिम्मेदारी भी अध्यापक की ही है। यह प्रशासनिक कार्य है, न कि शिक्षा से जुड़े काम हैं। और तो और, ग्रामीण स्तर पर संचालित की जाने वाली अनेक योजनाओं में अध्यापक का ही सहारा लिया जाता है। चाहे ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाने वाला टीकाकरण हो या बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों को आयरन एवं कैल्शियम की गोली बांटनी हो, यहां तक कि पेट के कीड़ों की गोलियां भी अध्यापक को ही बांटनी होती हैं। गैर-शैक्षणिक कार्य में अधिकतर स्कूल प्रबंधन, डेटा संग्रह और दस्तावेजीकरण शामिल होता है और कई बार इस कार्य में दोहराव और मात्रा ही अधिक होती है।

दिन में गैर-शैक्षणिक कार्य का बार-बार वितरण और उच्च अधिकारियों के कॉल पर तैयार रहने का दबाव अक्सर शिक्षकों पर बोझ डालता है और शिक्षण के मुख्य कार्य को पूरा करने में समय लगाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। यह सब ठीक किया जाना चाहिए। सीबीएसई की तरफ से कुछ समय पहले जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार-2009 के तहत किसी भी शिक्षक को गैर शिक्षण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यह भी कहा गया था कि टीचर्स को पढ़ाने, परीक्षा संचालन और जांच कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाए। लेकिन अब भी ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं। हमारे सरकारी और एडिड स्कूल इसका अपवाद नहीं हैं। पूरे विश्व में शिक्षा व्यक्ति के जीवन का आधार समझी जाती है। किसी भी ढांचे को खड़ा करने के लिए उसकी नींव को मजबूत किया जाना अति आवश्यक है। यदि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो किसी भी ढांचे का अधिक समय तक टिके रह पाना संभव नहीं। हमारे टीचर ही शिक्षा की नींव बनाते हैं। यदि हम बच्चों को क्वालिटी स्कूल एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो टीचरों को टीचर ही रहने दिया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षा पर फोकस बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। क्या उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं चाहिए? हमारे शिक्षकों को जब तक गैर शैक्षणिक कार्यों में फंसाकर रखा जाएगा, तो उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की उम्मीद बेमानी है। हमारे शिक्षक दबाव में रहते हैं क्योंकि गैर शिक्षण कार्यों से जुड़े हर एक आदेश का पालन कर उनको नौकरी भी बचानी होती है। इलेक्शन ड्यूटी में तो अनेक महिला अध्यापकों की हालत बहुत खराब हो जाती है। क्या ऐसी गैर शिक्षण गतिविधियों में महिला अध्यापकों को राहत की जरूरत नहीं है? पचास की उम्र पार कर चुकी महिलाओं को फील्ड में गैर शिक्षण

> "मिड डे मील की पूरी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक की ही होती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से बच्चों को दिए जाने वाली अनेक सुविधाएं जैसे स्कूल यूनिफार्म, जूते, मोजे, बैग, पुस्तकें इत्यादि की खरीद-फरोख्त एवं बांटने की जिम्मेदारी भी अध्यापक की ही है। यह प्रशासनिक कार्य है, न कि शिक्षा से जुड़े काम हैं। और तो और, ग्रामीण स्तर पर संचालित की जाने वाली अनेक योजनाओं में अध्यापक का ही सहारा लिया जाता है।

गतिविधियों से दूर रखना ठीक लगता है। याद रहे गैर शिक्षण कार्यों से जब स्कूल शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है, इसका असर अंततः बच्चों की दी जाने वाली शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी पड़ता है। शैक्षणिक समयावधि के बाद शिक्षकों से अन्य और तरह के कार्य कराया जाना क्या नैतिकता होगी? क्या यह मानवीय दृष्टिकोण होगा? क्यों न हम अपने शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों के डर से निकालने की पहल करें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया है कि गैर-शैक्षणिक कार्य शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसमें यह भी कहा गया है कि 'उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव ड्यूटी और सर्वेक्षण करने से संबंधित न्यूनतम कार्यों के अलावा शिक्षकों को स्कूल के समय के दौरान ऐसी किसी भी गैर-शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने के लिए न तो अनुरोध किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी जो शिक्षक के रूप में उनकी क्षमताओं को प्रभावित करती हो'। हमें प्रशासनिक कार्य करने के लिए स्कूलों में अधिक से अधिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में जहां दस्तावेजीकरण ऑनलाइन है, तब ऑफलाइन दस्तावेजीकरण को समाप्त किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्कूलों में, जहां इंटरनेट/आईटी कनेक्टिविटी नहीं है या सीमित है, इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए और ऑफलाइन दस्तावेजीकरण की अनुमति दी जा सकती है। जहां पहले से ही डेटा उपलब्ध है, वहां स्कूलों को इसे संकलित करने और भेजने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

चिंतन विचार

भारत के विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदम

त्रिलोक कपूर

भारत अब मूल विषयों के साथ विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री हर मंच से जिस वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, आज उन्हीं के नेतृत्व के कारण वो धारणा यथार्थ में परिवर्तित हो रही है। आज भारत विश्व गुरु बनने के संकल्प की ओर कदम बढ़ा रहा है। सचमुच हम इसी मजबूत नेतृत्व के साथ विश्व भर का नेतृत्व हर क्षेत्र में करेंगे। भारत के विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदम भारत की 140 करोड़ जनता की ताकत एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। विश्व के सबसे मजबूत समूह जी-20 की अध्यक्षता कर भारत की नेतृत्व क्षमता का लोहा पूरा विश्व अब मान रहा है। आज भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर उभरा है। डिजिटल क्रांति में अग्रणी होने के साथ-साथ पिछले नौ वर्षों में भारत विश्व पटल पर एक सुदृढ़ हस्ताक्षर बन कर उभरा है। कोविड वैक्सीनेशन में भारत ने जो असरदार काम मानवता के लिए किया, वो विश्व के अन्य देश भी नहीं कर सके। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पूरा विश्व यूक्रेन-रूस युद्ध के समाधान के लिए भारत की तरफ आस लगाए बैठा है।

जब एक ही सप्ताह इटली व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत की ताकत का लोहा मान कर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हों, तो हर भारतवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी में भारत अब मुशर्रफ और पाकिस्तान की मेजबानी नहीं करता, अपितु भारत विकसित राष्ट्रों के साथ कदमताल करते हुए नजर आ रहा है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज का अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के साथ केमिस्ट्री पूरे विश्व को एक संदेश था कि भारत अब मजबूत कदम से अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के कट्टर विरोधी तुर्किये भी जब भारत को दोस्त कह कर बुलाए तो कूटनीति की कुशलता समझ आती है। आज जब जी-20 शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है, दुनिया के शीर्ष देशों की प्रमुख हस्तियां इसमें शामिल होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, जर्मनी की चांसलर ओल्फ शोल्ज, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिस टरुडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन व जापान के प्रधानमंत्री समेत कई सदस्य देशों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। जी-20 में भारत के साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ आदि देश सम्मिलित हैं। यह बड़ी बात है कि दुनिया के कल्याण के लिए भारत में ये सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन तभी किसी देश में संभव है जब वो देश आतंकवाद की चपेट में न हो, आर्थिक पक्ष मजबूत हो और नेतृत्व क्षमता असाधारण हो।

भारत की जी-20 अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकों का आयोजन देश के विभिन्न शहरों में होगा। इसी कड़ी में जी-20 में विज्ञान व तकनीक विषयों संबंधित बैठकें अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निश्चित की गई हैं। इन बैठकों से हिमाचल, कांगड़ा व धर्मशाला को ग्लोबल पहचान मिलेगी, वहीं विज्ञान व तकनीक के विमर्श से कांगड़ा में रोजगार के द्वार खुलेंगे। धर्मशाला दलाई लामा के कारण वैश्विक राजनीति में एक बड़ा स्थान है। उसे दावोस की तर्ज पर विकसित करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ही सोच है। इन 200 बैठकों के बाद जी-20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर, 2023 को होगा। इसमें जी-20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के शीर्ष नेता व प्रमुख शिरकत करेंगे। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान सभी देशों के शीर्ष नेता जी-20 एजेंडा के आर्थिक पक्ष और दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जी-20 बैठकों के दौरान हुए विमर्श के बाद सांझा घोषणा की जाएगी। इन बैठकों से पहले ही योग, मोटे अनाजों, डिजिटल क्रांति के भारतीय सुझावों और नरेंद्र मोदी की सोच पर इन जी-20 देशों ने मोहर लगा दी है। समकालीन दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय दुनिया में बदल रही है। इस तरह के गतिशील अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक बहुपक्षीय मंच की उपस्थिति अपेक्षित थी, जहां संप्रभु राष्ट्र एक साथ आएं और निरंतर परिस्थितियों के माध्यम से विमर्श करते हुए मानव कल्याण के भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करते रहें।

इसी प्रयास का एक प्रासंगिक उदाहरण जी-20 है जहां सदस्य देश, महाद्वीपों और जनसांख्यिकी में फैले हुए हैं, एक साथ आते हैं, अपनी ताकत, समस्याएं, संघर्ष, चुनौतियों को साझा करते हैं और ऐसी नीतियां बनाते हैं जो विभिन्न भू-राजनीतिक और राजनीतिक-आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं।

ब्याज दरों में वृद्धि से सस्ते घर की बिक्री 15 फीसदी घटी, छोटे खरीदारों का हौसला पस्त

एनटीवी न्यूज

रिपोर्ट के अनुसार, 50 लाख रुपये से ज्यादा वाले होम लोन का हिस्सा चालू वित्त वर्ष में 15 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गया है। इससे यह पता चलता है कि कम कमाई वाले लोगों पर ब्याज दरों के बढ़ने का ज्यादा असर हुआ है जो सस्ते घर खरीदते हैं।

नई दिल्ली। पिछले साल से लगातार बढ़ रही ब्याज दरों ने छोटे घर खरीदारों का हौसला पस्त कर दिया है। जबकि महंगे घर खरीदने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी- फरवरी, 2023 में सभी शेडयूल्ड कमर्शियल बैंक (एएससीबी) की ओर से 30 लाख रुपये तक के नए दिए गए होम लोन का हिस्सा कुल कर्ज में घटकर 45 फीसदी हो गया है। जून तिमाही में यह हिस्सा 60 फीसदी का था।

रिपोर्ट के अनुसार, 50 लाख रुपये से ज्यादा वाले होम लोन का हिस्सा चालू वित्त वर्ष में 15 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गया है। इससे यह पता चलता है कि कम कमाई वाले लोगों पर ब्याज दरों के बढ़ने का ज्यादा असर हुआ है जो सस्ते घर खरीदते हैं। मई, 2022 से फरवरी, 2023 के बीच छह बार में आरबीआई ने रेपो दर में 2.50 फीसदी इजाफा किया है। अप्रैल, 2022 से जनवरी, 2023 के बीच 1.80 लाख करोड़ रुपये के हाउसिंग लोन बैंकों ने बांटे। 2021-2022 में इसी दौरान 1.40 लाख करोड़ रुपये के कर्ज दिए गए थे।

55 लाख वाले मकान खरीदारों में हुई वृद्धि

करीब 55 लाख होम लोन के खाते एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट्स (ईबीएलआर) से जुड़े हैं। होम लोन को अक्तूबर, 2019 में रेपो दर से जोड़ दिया गया था। रेपो दर में 2.50 फीसदी की वृद्धि से खुदरा ग्राहकों की किस्त के ब्याज में सालाना 16% का इजाफा होगा। आरबीआई के फैसले से होम लोन ग्राहकों के ब्याज में 20,000 करोड़ रुपये की बढ़त हो सकती है। केवल 8.2 लाख ही ऐसे होम लोन ग्राहक हैं, जो कर्ज का अग्रिम भुगतान (प्री-पेमेंट) कर सकते हैं।

इस तरह घर खरीदारों पर पड़ा ब्याज का असर

कुल होम लोन ग्राहक 1.15 करोड़

बकाया रकम 18.9 लाख करोड़ रुपये

ईबीएलआर का हिस्सा 48 फीसदी

ईबीएलआर से जुड़े होम लोन ग्राहक 55.2 लाख- बकाया रकम 9.1 लाख करोड़

47 लाख ग्राहकों ने किस्त, अवधि या फिर दोनों बढ़वाई, रकम 8.2 लाख करोड़ रही।

ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है, यह सिर्फ अमीरों को रिझाने का शिगूफा है या समय की जरूरत

एनटीवी न्यूज

प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग, जनसंख्या विस्फोट आदि जैसे कारकों ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में लोगों का रुझान ग्रीन अफोर्डेबल हाऊसिंग के प्रति बढ़ रहा है। अगर समय रहते हम इस ग्रीन हाउसिंग की अवधारणा पर आगे नहीं बढ़े तो पर्यावरण के लिहाज से हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

नईदिल्ली। ग्रीन हाउसिंग सिर्फ एक ग्रीन हाउस नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक जिम्मेदार, स्वस्थ और किफायती तरीका भी है! पर्यावरण के हिसाब से गैर-जिम्मेदार व्यवहार की भविष्य में क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, इस बारे में विचार करते हुए प्रकृति और इसके संसाधनों के साथ सद्भाव में रहना इसमें शामिल है। लोग अक्सर ग्रीन हाउसिंग से यह सोचकर दूर भागते हैं कि यह एक महंगा विकल्प है, जो केवल अमीरों के लिए है, लेकिन एक बार जब आप इसे बारीकी से देखते हैं, तो ग्रीन हाउसिंग वास्तव में लंबे समय में अधिक किफायती लग सकता है।

तो, आइए इसे और करीब से देखें। ग्रीन होम वास्तव में क्या है और अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं?

1800 के दशक के बाद से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग, जनसंख्या विस्फोट आदि जैसे कारकों ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाया है। जहां पहले हम कहीं दूर ग्लेशियरों के पिघलने और ओजोन परत को हो रहे नुकसान की बातें करते थे, वहीं अब हम रोजमर्रा के जीवन में मौसम के बदलाव और प्रदूषण के असर को महसूस कर सकते हैं। हमारी दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और अधिक टिकाऊ उपायों को अपनाने की आवश्यकता है और एक ग्रीन होम ठीक यही काम करता है!

होमफर्स्ट फाइनेंस कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर गौरव मेहता के अनुसार ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा घर है जिसमें टिकाऊपन होता है। जो पर्यावरण के अनुकूल और रिनुएबल निर्माण सामग्रियों से बना होता है। साथ ही यह पानी, ऊर्जा व कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। इसे हम ₹ग्रीन होम₹ भी कह सकते हैं। भले ही ग्रीन होम की अवधारणा सुनने में थोड़ा पेचीदा लगे पर इसे किफायती तरीके से भी अमल में लाया जा सकता है।

पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन का उपयोग करके, एएसी ब्लॉक, कृत्रिम रेत, एसआरआई पेंट, लो फ्लो फिक्स्चर जैसी ग्रीन निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल करके और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करके किफायत के साथ टिकाऊपन का लाभ उठाया जा सकता है। गौरव के अनुसार एक ग्रीन हाउस न केवल गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है, बल्कि इसके कई अन्य लाभ भी हैं, जो इस प्रकार हैं:

ऊर्जा की बचत करता है: ग्रीन होम्स को

इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर ऊर्जा की खपत को कम करते हैं, जैसे रोशनी के लिए दिन में सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करना और सौर वॉटर हीटर जैसे नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करना। यह पारंपरिक ऊर्जा के इस्तेमाल पर आपकी निर्भरता को कम करता है और साथ ही साथ बिजली के बिल को भी कम करता है। 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरणों, एलईडी लाइट्स आदि को अपनाने से आपको बहुत कम कीमत पर ऊर्जा बचाने में मदद मिल सकती है।

पानी बचाता है: ताजा पानी एक बहुत ही कीमती संसाधन है, जो तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। ग्रीन होम्स पानी के इस्तेमाल को और प्रभावी बनाते हैं। रेनवाटर हार्वेस्टिंग जैसे पानी बचाने के तरीके भूजल स्तर को रिचार्ज करने में मदद करते हैं, जबकि लो फ्लो फिक्स्चर और डुअल फ्लश शौचालय जैसे उपकरण दैनिक खपत को कम करने में मदद करते हैं।

स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता है: हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जब आप घर में होते हैं तो बाहर का वायु प्रदूषण आपको प्रभावित नहीं करता है। हालांकि, दुनिया भर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ने के चलते घर में भी प्रदूषण हमारे नियमित जीवन पर उतना ही असर डालता है, जितना कहीं और। इसी कारण श्वसन संक्रमण, हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर आम होता जा रहा है। एयर वेंटिलेटर लगाने से बिना किसी रुकावट के हवा के प्रवाह में मदद मिलती है, जबकि लो वीओसी पेंट में कम वाष्पशील रसायन होते हैं, जिससे हानिकारक रसायनों का उत्सर्जन सीमित हो जाता है। इस प्रकार ग्रीन हाउस न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि हमारे लिए भी स्वास्थ्यवर्धक हैं।

ग्रीन अफोर्डेबल होम का चुनाव कैसे करें?

ग्रीन अफोर्डेबल होम चुनने के दो तरीके हैं-

अपना खुद का ग्रीन होम बनाएं: चूंकि आप इसे सीधे जमीन से खड़ा करते हैं, आप अपने घर में टिकाऊ तरीकों और उपकरणों को अपनाने के लिए अपने आर्किटेक्ट से सलाह लें। इस तरह आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार टिकाऊ तरीकों को शामिल कर अपने हिसाब का ग्रीन होम बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने ग्रीन होम को संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित करवा सकते हैं। भारत में कुछ सबसे भरोसेमंद ग्रीन बिल्डिंग एजेंसियों में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंटल डिजाइन (LEED), ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) शामिल हैं। इससे आपको अपने ग्रीन होम के टिकाऊपन का मूल्यांकन करने और किसी भी सरकारी प्रोत्साहन का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है।

ग्रीन सर्टिफाइड अपार्टमेंट खरीदें: जब आप अपने लिए नया घर खोज रहे हों, तो अपने बिल्डर/ब्रोकर से गेटेड कम्युनिटी, नियमित जल आपूर्ति और पर्याप्त वेंटिलेशन के बारे में पूछताछ करते समय अमल में लाए गए ग्रीन उपायों के बारे में भी पूछें और यह भी सुनिश्चित करें कि बिल्डिंग को आईजीबीसी, आईएफसी, गृह आदि जैसे प्राधिकरणों से हरित प्रमाणन प्राप्त है या नहीं। इन संगठनों के द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपार्टमेंट की सुविधाओं का आकलन कर सकते हैं।

गौरव मेहता का मानना है कि जो लोग अपना नया घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ग्रीन होम बनाना या कम से कम बाद में ग्रीन उपायों को शामिल करने की गुंजाइश छोड़कर रखना बुद्धिमानी भरा निर्णय है। सभी देश पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, इस कारण ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर नियमन में दुनिया भर में व्यापक बदलाव आया है। भारत के द्वारा जी20 की अध्यक्षता संभालने के साथ ही हम ग्रीनर फ्यूचर की ओर चल पड़े हैं। अभी टिकाऊ सामग्रियों और उपकरणों का स्वैच्छिक उपयोग, आने वाले समय में अनिवार्य हो सकता है और इस तरह की दूरदर्शिता लंबे समय में गेम चेंजर साबित हो सकती है।

इनसाइड

विदेश में पढ़ाई, घूमना और पैसे भेजना होगा महंगा, 1 जुलाई से लगेगा भारी-भरकम टैक्स

एक जुलाई से विदेश में पढ़ाई और विदेश में पैसा भेजना महंगा हो जाएगा। इनकम टैक्स कानून की धारा 206 सी में संशोधन किया गया है। ऐसे में एक जुलाई से चिकित्सा और शिक्षा उद्देश्यों को छोड़कर किसी भी बाहरी रेमिटेंस के मामले में पूरे मूल्य पर 20 फीसदी का टीसीएस कटेगा।

नईदिल्ली : अगर आप विदेश यात्रा करने के शौकीन हैं या दूसरे देशों में पैसा भेजते रहते हैं, तो अब आपका खर्चा बढ़ने वाला है। एक जुलाई से विदेश में पैसा भेजने पर लगने वाला टैक्स बढ़ जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इसकी घोषणा की थी। सरकार ने विदेशी यात्रा पर ज्यादा टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स लॉ की धारा 206 सी में संशोधन किया है। एक जुलाई से ऐसे पेमेंट पर 20 फीसदी की दर से टीसीएस लगेगा। इस समय यह 5 फीसदी है। चिकित्सा और शिक्षा उद्देश्यों को छोड़कर किसी भी बाहरी रेमिटेंस के मामले में पूरे मूल्य पर 20 फीसदी का टीसीएस कटेगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (Liberalised Remittance Scheme) के तहत भारत से बाहर 7 लाख रुपये से ज्यादा की रकम भेजने पर 20% टीसीएस कटेगा। एक जुलाई 2023 से यह संशोधन लागू हो जाएगा।

एजुकेशन लिंक स्थापित हुआ तो कम टैक्स

इस टैक्स के दायरे में विदेशी दौरों, विदेशी मुद्रा की खरीदारी, दोस्तों या रिश्तेदारों को विदेश में उपहार भेजना और विदेशी स्टॉक खरीदना आदि भी शामिल हैं। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी खर्च के मामले में यदि माता-पिता यह स्थापित करने में सक्षम हैं कि राशि शिक्षा के उद्देश्य के लिए है, तो कुल राशि 7 लाख रुपये से अधिक होने पर टीसीएस 5 फीसदी होगा। यदि राशि ट्यूशन फीस या छात्रावास के खर्च के लिए है, तो एजुकेशन लिंक स्थापित करना आसान है। लेकिन यदि छात्र विदेश में पढ़ाई के दौरान कैंपस से दूर किराए के आवास में रह रहा है तो यह आसान नहीं है। यदि एजुकेशन लिंक स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो बिना किसी सीमा के 20 फीसदी का टीसीएस देना होगा।

महंगी हो जाएगी विदेश में पढ़ाई

प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कंपनी एम स्क्वायर मीडिया (MSM) के सीईओ और संस्थापक संजय लॉल ने कहा, 'टैक्स भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई की लागत में वृद्धि करेगा। इसका विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में और हम उन देशों में छात्रों की वरीयता में बदलाव देख सकते हैं, जहां शिक्षा की लागत तुलनात्मक रूप से कम है।' उन्होंने कहा कि यह देखा जाना बाकी है कि ये उपाय भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह और विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसरों की तलाश करने वाले भारतीय छात्रों की प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित करेंगे।

अप्रैल से फरवरी के बीच निर्यात 7.5 फीसदी बढ़कर 406 अरब डॉलर, आयात में 19 फीसदी की तेजी

विनिर्माण गतिविधियों में कमजोरी से देश का निर्यात सालाना आधार पर लगातार तीसरे महीने गिरा है। फरवरी, 2023 में यह 8.8 फीसदी घटकर 33.88 अरब डॉलर रह गया है जो फरवरी, 2022 में 37.15 डॉलर था।

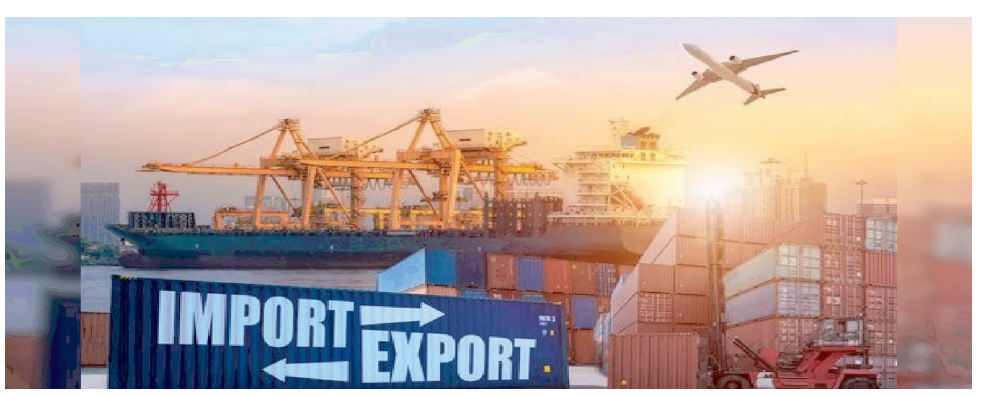

नई दिल्ली। पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी के बीच देश का निर्यात 7.5 फीसदी बढ़कर 405.94 अरब डॉलर रहा है। इस दौरान आयात भी 18.82 फीसदी बढ़कर 653.47 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि आंकड़े बहुत उत्साहजनक हैं। हम गति बनाए रखने में सक्षम हैं। इस रुझान को देखते हुए कह सकते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में 750 अरब डॉलर के निर्यात के आंकड़े को पार कर जाएंगे। विनिर्माण गतिविधियों में कमजोरी से देश का निर्यात सालाना आधार पर लगातार तीसरे महीने गिरा है। फरवरी, 2023 में यह 8.8 फीसदी घटकर 33.88 अरब डॉलर रह गया है जो फरवरी, 2022 में 37.15 डॉलर था। उधर, आयात भी इसी दौरान 8.21 फीसदी गिर कर 51.31 अरब डॉलर रह गया जो एक साल पहले समान अवधि में 55.9 अरब डॉलर था।

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश का व्यापार घाटा फरवरी में 17.43 अरब डॉलर रहा है जो एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 के बीच जिन क्षेत्र में गिरावट रही उसमें प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग, जेम्स एवं जूलरी और सोना शामिल रहे। बढ़त वाले क्षेत्रों के आयात में कच्चा तेल, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, केमिकल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल, तैयार कपड़े और टेक्सटाइल्स रहे।

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि हमने वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गति बनाए रखी है। निर्यातकों ने भी गति बनाए रखी है। सेवा निर्यात बहुत अच्छा कर रहा है। व्यापार घाटा वास्तव में कम हुआ है। उम्मीद है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष के लिए भी लक्ष्य तय करने की कवायद शुरू कर दी है।

पाम तेल आयात 30% गिरकर आठ माह के निचले स्तर पर

कमजोर मांग से देश में पाम तेल का आयात फरवरी में 30 फीसदी गिरकर 5.86 लाख टन रह गया है। यह जून, 2022 के बाद का निचला स्तर है। हालांकि, कीमतें कम होने से नवंबर, 2022 से जनवरी, 2023 के बीच पाम तेल के आयात में 86% का उछाल आया था। अब कारोबारी पहले के भंडार को खाली कर रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बताया कि नवंबर और जनवरी में ज्यादा आयात के कारण फरवरी में कम आयात हुआ। सोया तेल का आयात तीन फीसदी गिरकर 3.55 लाख टन, सूरजमुखी तेल का आयात 66 फीसदी घटकर 1.56 लाख टन रह गया। खाने के तेल का आयात फरवरी में 12% बढ़कर 10.98 लाख टन रहा है। फरवरी, 2022 में यह 9.83 लाख टन था। तेजी इसलिए आई क्योंकि कच्चे पाम तेल का ज्यादा आयात किया गया था।

गैर खाद्य तेल का आयात 36,389 टन से घटकर 16,006 टन रह गया है। नवंबर, 2022 से फरवरी, 2023 के दौरान खाने के तेल का आयात बढ़कर 58.44 लाख टन पहुंच गया जो पहले के साल की समान अवधि में 45.91 लाख टन था।

वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं, परिवहन मंत्रालय ने कही ये बात

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि ट्रैक्टर एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरू में 15 साल के लिए पंजीकृत किया जाता है।

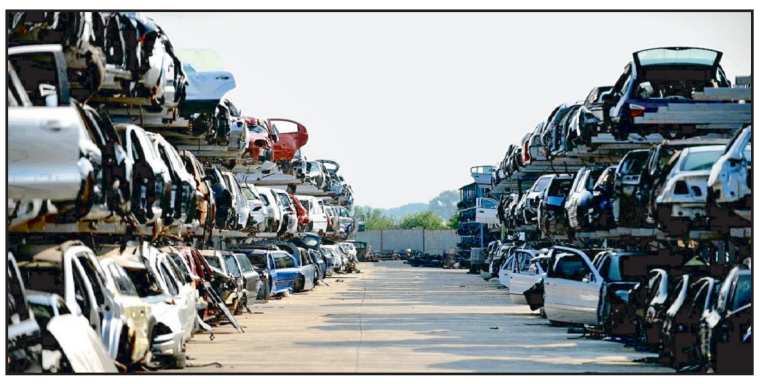

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि ट्रैक्टर एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरू में 15 साल के लिए पंजीकृत किया जाता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 15 साल की प्रारंभिक पंजीकरण अवधि पूरी होने के बाद इसके पंजीकरण को एक बार में पांच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए कोई अनिवार्य आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परिवहन मंत्रालय ने यह बात ट्रैक्टरों की स्क्रैप आयु 10 वर्ष होने की खबरें आने के बाद कही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि ट्रैक्टर एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरू में 15 साल के लिए पंजीकृत किया जाता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 15 साल की प्रारंभिक पंजीकरण अवधि पूरी होने के बाद इसके पंजीकरण को एक बार में पांच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा, "15 साल बाद ट्रैक्टरों को अनिवार्य रूप से कबाड़ में बदलने के संबंध में ट्विटर और व्हाट्सएप सहित मीडिया के एक निश्चित वर्ग में प्रसारित खबरें पूरी तरह से गलत, निराधार और बिना किसी सच्चाई के हैं

इसमें चेतावनी दी गई है कि दहशत पैदा करने के लिए झूठी सूचना फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने कुछ सरकारी वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन की स्क्रैपिंग के लिए आयु निर्धारित नहीं की है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

दूसरे साल भी भारत ने चीन को पछाड़ा, 2022 में देश में बने 23 यूनिकॉर्न, 18 फीसदी की वृद्धि

आईवीसीए-बैन एंड कंपनी की जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है भारत में ऐसे यूनिकॉर्न की संख्या 96 हो गई है। हालाँकि, इस वर्ष की संख्या 2021 में बनाए गए 44 यूनिकॉर्न की तुलना में आधी है। उस वर्ष कुल 73 यूनिकॉर्न देश में थे।

नई दिल्ली। भारत ने 2022 में 23 यूनिकॉर्न जोड़कर चीन को लगातार दूसरी बार पीछे छोड़ दिया है। चीन ने इसी दौरान केवल 11 यूनिकॉर्न बनाए हैं।

आईवीसीए-बैन एंड कंपनी की जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है भारत में ऐसे यूनिकॉर्न की संख्या 96 हो गई है। हालाँकि, इस वर्ष की संख्या 2021 में बनाए गए 44 यूनिकॉर्न की तुलना में आधी है। उस वर्ष कुल 73 यूनिकॉर्न देश में थे। रिपोर्ट के अनुसार, 23 यूनिकॉर्न में से नौ शीर्ष 3 महानगरों के बाहर के शहरों से निकले हैं। इसका मतलब है कि गैर-महानगरों में स्टार्टअप की कुल फंडिंग में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस साल भी कई निवेशकों ने अपना सबसे बड़ा फंड भारत केंद्रित स्टार्टअप से जुटाया है। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में देश में वेंचर कैपिटल निवेश (वीसी) में बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि वृहद आर्थिक अनिश्चितता और मंदी की आशंकाओं ने निवेश की गति को प्रभावित किया। देश में 2021 में स्टार्टअप के सौदों का मूल्य 38.5 अरब डॉलर था जो 2022 में घटकर 25.7 अरब डॉलर रह गया। सौदों में ज्यादा गिरावट दूसरी छमाही यानी अक्तूबर से मार्च के दौरान देखी गई।

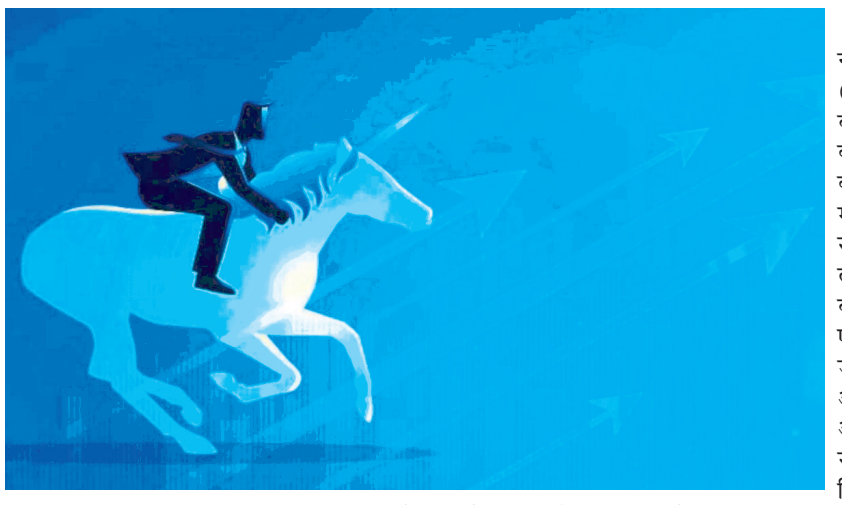

सरकार जुटा सकती है 15.43 लाख करोड़

सरकार अगले वित्त वर्ष में बाजार से 15.43 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखी है। यह कुल उधारी का करीब 55 से 58% होगा। चालू वित्त वर्ष में 14.21 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य था। दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस पर अंतिम निर्णय 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैठक में लिया जाएगा। सरकार हालांकि इस दौरान कोई 20 या 50 साल वाले बॉन्ड्स को लॉन्च नहीं करेगी क्योंकि पहले के बॉन्ड्स से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस साल सरकार 160 अरब रुपये हरित बॉन्ड्स से जुटाई है।

नई विदेश व्यापार नीति इस महीने के अंत तक

सरकार इस महीने के अंत तक नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) जारी कर सकती है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर यह नीति होगी। मंत्रालय 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को दो लाख डॉलर ले जाने का लक्ष्य बना रहा है।

सरकार इस महीने के अंत तक नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) जारी कर सकती है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर यह नीति होगी। मंत्रालय 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को दो लाख डॉलर ले जाने का लक्ष्य बना रहा है। बर्थवाल ने कहा, हमने अपना एफटीपी तैयार किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह इस महीने के अंत तक जारी हो जाएगी। एफ़टीपी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेगी।

एलआईसी ने एनएमडीसी में बेची दो फीसदी हिस्सा

एलआईसी ने एनएमडीसी में दो फीसदी हिस्सा 700 करोड़ रुपये में बेच दिया है। शेयर बाजारों से मिली जानकारी के मुताबिक, 14 मार्च तक एलआईसी का हिस्सा 11.69% रहा है जो पहले 13.69 फीसदी था। इसे 119.37 रुपये प्रति शेयर पर बेचा गया है।

वेदांता ने चुकाया 10 करोड़ डॉलर का कर्ज

वेदांता लि. ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का 10 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाया है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि यह कर्ज का अग्रिम भुगतान है और निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह फैसला किया है। भुगतान की तारीख 31 मार्च थी, उससे पहले ही इसे पूरा कर दिया।

जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में 4 सदस्य

जीएसटी के विवादों को निपटाने के लिए हर राज्य में चार सदस्यों वाले एक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, इसमें दो तकनीकी अधिकारी और दो न्यायिक सदस्य होंगे। दो विभागीय बेंच भी होगी।

सिसोदिया पर अब विरोधियों की जासूसी का मामला

क्या है फीडबैक यूनिट केस, CBI की FIR में क्या है?

पी.वी. न्यूज

बुधवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और अन्य पर केस दर्ज कर लिया। इसके साथ ही 'फीडबैक यूनिट' में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है।

नई दिल्ली। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब नई मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की 'फीडबैक यूनिट' में कथित अनियमितताओं को लेकर सिसोदिया के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। पिछली महीने ही फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी थी।

फीडबैक यूनिट केस क्या है? यह मामला सामने कैसे आया? अभी इसमें क्या हुआ है? आइये जानते हैं'

फीडबैक यूनिट केस क्या है?

2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था। सरकार का कहना था इससे उनकी मंशा ये है कि विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखी जा सके। हालांकि, बाद में सरकार पर आरोप लगा कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी।

दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की। 2016 में एजेंसी की ओर से कहा गया कि सौंपे गए कार्य के अलावा, फीडबैक यूनिट ने प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों की जासूसी की। सीबीआई के मुताबिक, आठ महीने के दौरान फीडबैक यूनिट ने 700 से अधिक मामलों की जांच की थी। इनमें से 60 प्रतिशत मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई।

मामला सामने कैसे आया?

बताया जाता है कि फीडबैक यूनिट की स्थापना के लिए कोई प्रारंभिक मंजूरी नहीं ली गई थी, लेकिन अगस्त 2016 में सतर्कता विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल तत्कालीन एलजी नजीब जंग के पास भेजी गई। जंग ने दो बार फाइल खारिज कर दी। इसी बीच एलजी ने फीडबैक यूनिट में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई और मामले को सीबीआई को सौंप दिया।

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने में नुकसान का भी जिक्र किया था। एजेंसी की मानें तो फीडबैक यूनिट के गठन और काम करने के गैरकानूनी तरीके से सरकारी खजाने को लगभग 36 लाख रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई ने कहा था कि किसी अधिकारी या विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

फरवरी में फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अनुसार मनीष सिसोदिया पर विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगा। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम पर केस चलाने की अनुमति मांगी।

इसके बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गृहमंत्रालय के जरिए मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी। फीडबैक यूनिट सिसोदिया के ही अधीन काम कर रही थी। सीबीआई ने तत्कालीन सतर्कता निदेशक सुकेश कुमार जैन, फीडबैक यूनिट के संयुक्त निदेशक और सीएम के विशेष सलाहकार राकेश कुमार सिन्हा, फीडबैक यूनिट के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार पुंज और सतीश खेत्रपाल और गोपाल मोहन के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मंजूरी मांगी थी। गोपाल मोहन भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार के रूप में काम करते हैं।

फीडबैक यूनिट केस में अभी क्या हुआ है?

मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और अन्य पर केस दर्ज कर लिया। इसके साथ ही सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। नई दिल्ली के सीबीआई-एसीबी थाने में दर्ज मामले में सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक षड़यंत्र, संपत्ति के गबन, लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग करना, खातों में फर्जीवाड़ा और लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार जैसे आरोप लगाए हैं।

सिसोदिया के अलावा और किन लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है?

एफआईआर में छह लोगों के नाम दर्ज हैं। इसके साथ ही अन्य अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं, उनमें'

1. मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम
2. सुकेश कुमार जैन, तत्कालीन सचिव सतर्कता विभाग
3. राकेश कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार और संयुक्त निदेशक, फीडबैक यूनिट
4. प्रदीप कुमार पुंज उप निदेशक, फीडबैक यूनिट
5. फीड बैक ऑफिसर के पद पर कार्यरत सतीश खेत्रपाल
6. गोपाल मोहन, दिल्ली के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार विरोधी सलाहकार
7. अज्ञात अन्य

सीआर पाटिल बन सकते हैं राजस्थान प्रभारी, गुजरात भाजपा अध्यक्ष को जन्मदिन पर पीएम दे सकते हैं ये तोहफा!

नई दिल्ली। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल (CR Patil) को उनके जन्मदिन (16 मार्च) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी जिम्मेदारियों का तोहफा मिल सकता है। उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान का प्रभारी बनाया जा सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को एतिहासिक बहुमत दिला चुके सीआर पाटिल के सामने राजस्थान में 'वसुंधरा फैक्टर' से निपटते हुए पार्टी को बड़ी जीत दिलाने की चुनौती होगी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से इसकी सहमति मिल चुकी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जा सकती है।

सीआर पाटिल को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं के रूप में देखा जाता है। सूरत के नवसारी लोकसभा क्षेत्र से 2009 से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीत चुके पाटिल को चुनावी रणनीति बनाने में माहिर समझा जाता है। पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी देकर 'हर बूथ पर जीत' हासिल करने की भाजपा की माइक्रो लेवल की चुनावी रणनीति को सीआर पाटिल के दिमाग की ही उपज मानी जाती है। दिल्ली में हुई पार्टी की भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआर पाटिल के काम की खुलकर प्रशंसा की थी।

गुटबाजी से निपटने की चुनौती

राजस्थान में भाजपा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया स्वयं को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर रही हैं तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा के कई गुटों को साथ लाकर चुनाव में जीत हासिल करना सीआर पाटिल के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। वहीं, चर्चा है कि राजस्थान के वर्तमान प्रभारी अरुण सिंह को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। उनके पास कर्नाटक राज्य का अतिरिक्त प्रभार है और वे पार्टी में महासचिव के पद पर भी हैं। चार महत्त्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।

कैसे बने मोदी के करीबी

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, वे पूर्व केंद्रीय मंत्री काशीराम राणा का हाथ पकड़ कर राजनीति में आए थे। जब गुजरात में 'केशूभाई पटेल बनाम नरेंद्र मोदी' की राजनीति चली, पाटिल ने मोदी का दामन थाम लिया और उनके करीबियों में शामिल हो गये। जब नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया, उन्हें उनके लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। यहां से शानदार जीत हासिल करने के बाद पाटिल प्रधानमंत्री के और ज्यादा करीबी और विश्वसनीय लोगों में शुमार हो गए।

मनरेगा के बजट अनुमान में कटौती पर संसदीय समिति ने जताई चिंता, कही ये बात

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल में मनरेगा की भूमिका बेहद अहम रही और यह जरूरतमंद लोगों के लिए संकट काल में यह योजना आशा की किरण बनी।

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट अनुमान में कटौती पर चिंता व्यक्त की है। लोकसभा में बुधवार को समिति की रिपोर्ट पेश हुई। इस दौरान समिति की अध्यक्ष द्रमुक सांसद कनिमोई करूणानिधि ने मनरेगा को बेरोजगार वर्ग के लिए संकट काल में आशा की किरण बताया और इस बात पर चिंता व्यक्त की कि वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2023-24 में मनरेगा के बजट अनुमान में 29400 करोड़ रुपए की कटौती की गई है।

कोरोना काल में बढ़ा मनरेगा में बजट आवंटन

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल में मनरेगा की भूमिका बेहद अहम रही और यह जरूरतमंद लोगों के लिए संकट काल में यह योजना आशा की किरण बनी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020-21 में योजना में आवंटित रकम 61,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपए किया गया। वहीं 2021-22 में योजना के तहत आवंटित 73 हजार करोड़ को बढ़ाकर 99,117 करोड़ रुपए किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा की राशि 73 हजार करोड़ से बढ़ाकर 89400 करोड़ रुपए की गई।

बजट अनुमान में 29400 करोड़ रुपए की कटौती

रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरंभिक स्तर पर ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रूपये की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है 'समिति मनरेगा के तहत आवंटन में कमी के औचित्य को समझ नहीं पायी है।' रिपोर्ट में सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने की अपील की गी है। समिति ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और संशोधित अनुमान स्तर पर धनराशि में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन फिर भी मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ग्रामीण विकास विभाग ने किस प्रकार मनरेगा के प्रस्ताव के चरण में 98,000 करोड़ रूपये की मांग की गणना की।

समिति ने सिफारिश करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग जमीनी स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत काम की मौजूदा भारी मांग का अधिक सटीकता से अनुमान लगाए और अपने पत्राचार एवं प्रशासनिक कौशल द्वारा वित्त मंत्रालय से मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि की मांग करे।

'G20 की अध्यक्षता 140 करोड़ भारतीयों की ताकत दिखाती है', संयुक्त राष्ट्र में बोलीं भारत की प्रतिनिधि

रुचिरा कंबोज ने कहा कि जी20 के आयोजनों में भारत निजी क्षेत्र, यूनिवर्सिटीज, सिविल सोसाइटी और युवाओं को शामिल कर वैश्विक मुद्दों पर एक नई सोच पैदा कर रहा है।

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को कहा कि भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है और यह भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत को दिखाता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने जी20 को लोगों का जी20 बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक अनौपचारिक बैठक के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने ये बातें कही।

'भारत ने बनाया लोगों का जी20'

उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता करना 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को दर्शाता है। हम जी20 को देश के लोगों तक लेकर गए हैं और हम इसे लोगों का जी20 बना रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हमने कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं, जिनमें विदेश मंत्रियों की बैठक, वित्त मंत्रियों की बैठक और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठकें शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर

रुचिरा कंबोज ने कहा कि जी20 के आयोजनों में भारत निजी क्षेत्र, यूनिवर्सिटीज, सिविल सोसाइटी और युवाओं को शामिल कर वैश्विक मुद्दों पर एक नई सोच पैदा कर रहा है। कंबोज ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लैंगिक समानता की दिशा में काम कर रहे हैं और इसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, माई गवर्नमेंट जैसे कार्यक्रमों का अहम योगदान है। भारतीय राजदूत ने कहा कि उनकी सरकार ने कई ऐसे नागरिक केंद्रित डिजिटल पहल की है, जिनका फोकस महिलाओं को आर्थिक, तकनीकी और रोजगार के स्तर पर सक्षम बनाना है।

एक दिसंबर से जी20 की अध्यक्षता कर रहा भारत

बता दें कि एक दिसंबर से दुनिया के शक्तिशाली समूह जी20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के दुनिया में बढ़ते महत्व को दर्शाने के लिए जी20 का वैश्विक मंच महत्वपूर्ण है और भारत की भी कोशिश है कि इस मंच का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। जी20 में दुनिया के वो देश शामिल हैं, जिनकी कुल जीडीपी, दुनिया की कुल जीडीपी की 85 फीसदी है। जी20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्किए, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं।

देशभर में क्यों खाली पड़े हैं स्टेशन मास्टर के 5353 पद, भारतीय रेलवे ने बताई इस तरह की वजह

पी.वी. संवाददाता

बुधवार को बहुजन समाजवादी पार्टी के अमरोहा से लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने रेल मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछा। सांसद अली ने सरकार से सवाल किया कि रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों की भारी कमी है। इनकी भर्ती के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार में रेलवे की जॉब सबसे अच्छी नौकरियों में से एक मानी जाती है। रेलवे में भी कई ऐसी पोस्ट होती हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं। इन्हीं में से ही एक पोस्ट है स्टेशन मास्टर। कई उम्मीदवार रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन इन दिनों रेल मंत्रालय स्टेशन मास्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। देशभर में 5353 स्टेशन मास्टरों के पद खाली पड़े हैं। बुधवार को बहुजन समाजवादी पार्टी के अमरोहा से लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने रेल मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछा। सांसद अली ने सरकार से सवाल किया कि रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों की भारी कमी है। इनकी भर्ती के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही अभी स्टेशन मास्टर के कितने पद खाली हैं। सांसद अली के सवाल पर रेल मंत्रालय ने जवाब दिया कि, एक फरवरी 2023 की स्थिति के मुताबिक भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के 41884 पद स्वीकृत हैं। इनमें 36531 ऑनरोल है। जबकि 5353 रिक्त पद हैं। सभी श्रेणियों में स्टेशन मास्टर के जितने पद मौजूदा समय में परिचालन के जरुरी हैं, उनकी वास्तविक संख्या तय पदों से ज्यादा होती है। इसी वजह से स्टेशन मास्टर के कुल पदों की संख्या में 30 से 12.5 फीसदी तक घटती-बढ़ती रहती हैं। रेलवे कहना है कि मंत्रालय में पदों का रिक्त होना और उनका भरा जाना सतत प्रक्रिया है। इन्हें रेलों द्वारा परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों को मांगपत्र भेजकर भरा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, पद रिक्त होते हैं और उन्हें बाद में भरा जाता है। स्टेशन मास्टरों की 6865 रिक्तियों को केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) सं. 01/2019 – गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (एनटीपीसी) के तहत अधिसूचित किया गया था। तथा मांग पत्र भेजने वाली रेलों को इनके पैनल पहले ही भेज दिए गए हैं।

स्टेशन मास्टर बनने के लिए होना चाहिए ये योग्यता

रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दी जाती है। स्टेशन मास्टर पदों पर भर्ती, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के तहत की जाती है। यह परीक्षा पांच चरणों में होती है। इनमें दो ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल होता है। पहले दो चरण की ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है। इसके बाद एप्टीट्यूड और टाइपिंग टेस्ट देना होता है।

जमीन के बदले नौकरी मामले में CBI के सामने 25 मार्च को पेश होंगे तेजस्वी

नई दिल्ली। तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई समन पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि सीबीआई द्वारा फिलहाल गिरफ्तार ना करने के वादे के बाद तेजस्वी पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वह बिहार के उपमुख्यमंत्री को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए। तेजस्वी यादव 25 मार्च को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में सुबह साढ़े दस बजे पूछताछ के लिए पेश होंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई समन पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए समन जारी किया था। तेजस्वी यादव के वकील ने बताया कि वह 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना है। तेजस्वी के वकील ने आशंका जाहिर की थी कि तेजस्वी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि बस चाहते हैं कि तेजस्वी पेश हों ताकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाए जा सकें। सीबीआई ने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

क्या है तेजस्वी की याचिका में

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है।

दो साल में असम सरकार ने विज्ञापन पर 131 करोड़ रुपये खर्च किए

नई दिल्ली। असम विधानसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सूचना और जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने बताया कि साल २०२१-२२ और २०२२-२३ के लिए राज्य सरकार ने कुल १३१ करोड़ रुपये विज्ञापन के लिए जारी किए थे। जिसमें पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान कुल १३०.५९ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। असम सरकार ने पिछले दो सालों में विज्ञापन पर १३०.५९ करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को काफी पीछे छोड़ दिया है। सोनेवाल के पांच साल के कार्यकाल में १२५.६ करोड़ रुपये खर्च किए थे। असम विधानसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सूचना और जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने बताया कि साल २०२१-२२ और २०२२-२३ के लिए राज्य सरकार ने कुल १३१ करोड़ रुपये विज्ञापन के लिए जारी किए थे। जिसमें पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान कुल १३०.५९ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पांच साल के कार्यकाल में सरकार ने १३१.३ करोड़ रुपये विज्ञापन के लिए जारी किए थे। इसमें से १२५.६ करोड़ रुपये खर्च किए गए। अब सोनोवाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023